[Shri D. R. Chavan] Food and Agriculture (Department of Food);—

(i) Notification G.S.R. No. 387, dated the 4th March, 1965, publishing the Orissa Rice Procurement (Levy) Third Amendment Order, 1965.

(ii) Notification G.S.R. No. 389, dated the 6th March, 1965, publishing the Indian Jowar (Prohibition of use in manufacture of starch) Order, 1965. [Placed in Library. *See* No. LT-3999/65 for (i) and (ii)]

NOTIFICATION UNDER THE CUSTOMS ACT, 1962

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI B. R. BHAGAT): Madam, on behalf of Shri Rameshwar Sahu, I beg to lay on the Table, under section 159 of the Customs Act, 1962, a copy of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification S.O. No. 426, dated the 6th February. 1965. [Placed in Library. *See* No. LT-4003/65.]

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

I. THE APPROPRIATION (RAILWAYS) BILL,1965

II. THE APPROPRIATION (RAILWAYS) No. 2BILL, 1965

SECRETARY: Madam, I have to report to the House the following two Messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:—

(I)

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith a copy of the Appropriation (Railways) Bill, 1965, as passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 15th March, 1965.

The Speaker has certified that tbis Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

(ID

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith a copy of the Appropriation (Railways) No. 2 Bil!, 1965, as passed by the Lok Sabha at its silting held on the 15th March, 1965.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Madam, I beg to lay a copy of each of the Bills on the Table.

THE BUDGET (GENERAL), 1965-66— GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

श्री ए० बी० वाजपेयी (उत्तर प्रदेश) : महोदया, इसके पहले कि मैं बजट के बारे में कुछ कहूं, कल इस सदन में श्री नौशेर अली ने जो भाषण दिया है, उसकी ओर मैं सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं । मुझे खेद है कि मैं उनके भाषण के समय उपस्थित नहीं था, किन्तु उस भाषण की रिपोर्ट मैंने बाद में पढ़ी है और उसे पढ़ कर मुझे बड़ा धक्का लगा है । भारत का कोई नागरिक और उस पर भी संसद् का एक सदस्य सदन में ऐसा वक्तव्य करे, जिस से कम्यूनिस्ट चीन को सहायता मिले, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है । उन्होंने कहा, चीन हमारा शत्रु नहीं है । उन्होंने यह भी कहा कि भारत की और कम्यूनिस्ट चीन की सीमा तय नहीं है । इतना ही नहीं, उन्होंने चीन का पक्ष लेने के लिये यहां तक कहा कि हम जो सीमा पर अपनी सेनाएं इकट्ठी कर रहे हैं, उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि

ये सेनायें चीन पर आक्रमण करने के लिये इकट्ठी की जा रही हैं । उन्होंने यह भी मानने से इन्कार किया कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया है और यह भी कहा है कि कोई कम्यूनिस्ट देश किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं कर सकता । सदन में ऐसी भावनाओं का प्रकटीकरण बड़ा आपत्तिजनक है । वे सदन में उपस्थित नहीं हैं । वे एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं । मैं कड़े शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता । किन्तु जो भावनाएं उन्होंने प्रकट की हैं, वे भावनाएं देशभक्ति से मेल नहीं खातीं । उनके भाषण ने सरकार द्वारा वामपक्षी कम्यूनिस्टों के खिलाफ उठाये गये कदम की सार्थकता सिद्ध कर दी है । गृह-मंत्री ने जो वक्तव्य दिया और उसमें जो तथ्य दिये हैं, यदि हम उन तथ्यों की चर्चा न भी करें और जो तथ्य गृह-मंत्री ने सदन और देश के सामने नहीं रखे और जो गृह-मंत्री दावा करते हैं कि उनके पास हैं, यदि हम उनकी भी उपेक्षा कर दें, तो कल श्री नौशेर अली का भाषण ही ऐसा था, जिस से यह स्पष्ट है कि देश में एक ऐसा वर्ग है जो आक्रमणकारियों के साथ गठबन्धन में है और जो समय आने पर हमारी स्वाधीनता, हमारी अखंडता के खिलाफ सक्रिय षडयंत्र करने से संकोच नहीं करेगा । शासन को और सदन को भी उनके भाषण पर और उससे मिलने वाले खतरे के संकेत पर गंभीरता से विचार करना होगा ।

जहां तक बजट का न्धम्सब है, उस पर हमारे वित्त-मंत्री के व्यक्तित्व की पूरी छाप है । एक चतुर जादूगर की तरह से उन्होंने अपना मायाजाल फैलाने का यत्न किया है और यह आभास उत्पन्न करने की कोशिश की है कि देश संकट की घाटी में से निकल कर प्रगति के पठार पर आ गया है और अब समृद्धि का शिखर कोई बहुत दूर नहीं है । एक दृष्टि से वित्त-मंत्री की जादूगरी मैं समझ सकता हूं; क्योंकि देश में आज विश्वास का संकट है, क्राइसिस आफ कांफिडेंस है, और वित्त-मंत्री ने ऐसा बजट पेश किया है जिससे समाज के हर एक वर्ग के खोये हुये विश्वास को पुनः जगाने की चेष्टा की है । लेकिन कठिनाई यह है कि वित्त-मंत्री का आशावाद यथार्थ से मेल नहीं खाता ।

चालू वर्ष आर्थिक और वित्तीय दृष्टियों से बड़ा असंतुलित रहा है । भीषण अन्न का संकट, असाधारण मंहगाई, मूल्यों में वृद्धि, विदेशी मुद्रा का ह्रास, बाजार की गिरती हुई हालत और जिस मात्रा में पूंजी का एकत्रीकरण होना चाहिये, उसमें पूंजी निवेश का न होना, यह बताता है कि हमारी आर्थिक स्थिति अभी संकटापन्न है और जो आशाएं वित्त-मंत्री बंधाना चाहते हैं, उनके लिये कोई ठोस आधार नहीं है ।

वित्त-मंत्री जी ने दावा किया है कि राष्ट्रीय आमदनी में साढ़े चार फी सदी की वृद्धि हुई है और पिछले तीन वर्षों की तुलना में, जब यह वृद्धि ढाई फी सदी थी, साढ़े चार फी सदी की वृद्धि हमें संतोष दे सकती है । लेकिन साढ़े चार फी सदी की वृद्धि पर्याप्त नहीं है । यह न तो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगी और न इससे जनता की अपेक्षाएं ही पूर्ण होंगी । साढ़े चार फी सदी की वृद्धि से तो हम केवल अपना कर्जा लौटा सकते हैं । देश में ऐसे समाज की रचना के लिये, जिस में समृद्धि और समता होगी, हम इस वृद्धि का उपयोग नहीं कर सकेंगे । यदि हम और विकसित देशों की तुलना न भी करें, जैसे जापान में प्रति वर्ष 15 फी सदी और इटली तथा जर्मनी में क्रमशः 11 प्रति शत और 14 प्रति शत राष्ट्रीय आमदनी में वृद्धि हो रही है, किन्तु यदि हमें आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना है और हर व्यक्ति के लिए एक न्यूनतम जीवनस्तर की गारंटी देनी है, तो राष्ट्रीय आय में कम से कम 7 या 8 फी सदी प्रति वर्ष की वृद्धि होनी चाहिये । कल श्री भगत ने कहा कि हम 5 प्रति शत की वृद्धि कर लेंगे और चौथी पंचवर्षीय योजना में जो 3,000 करोड़ रु० की कमी है, उसको इससे पूरा कर

[श्री ए० बी० वाजपेयी]

लिया जायेगा । मुझे इसमें सन्देह है । चौथी पंचवर्षीय योजना का जो खाका या उसके संबंध में योजना आयोग द्वारा तैयार किया हुआ जो स्मृति-पत्र हमारे सामने आया है, उससे ऐसा लगता है कि योजना आयोग न तो कुछ सीखने के लिये तैयार है और न कुछ भूलने के लिये तैयार है । योजना आयोग अपनी असफलताओं का शिकार हो गया है और अपनी भूलें देखने के लिये तैयार नहीं है। इस स्मृति-पत्र के अनुसार 3,000 करोड़ रु० नये टैक्सों से उगाहा जायेगा और इतनी ही राशि की . . .

योजना मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : टैक्स से नहीं ।

प्रो० मुकुट बिहारी लाल (उत्तर प्रदेश) : इन टैक्सों के बाद एक्स्ट्रा टैक्स लगाये जायेंगे ।

श्री ए० बी० वाजपयी : नहीं, मैं श्री भगत की बात नहीं कर रहा हूं । मैं स्मृति-पत्र में चौथी पंचवर्षीय योजना के जो आंकड़े दिये गये हैं, उनका उल्लेख कर रहा हूं ।

प्रो० मुकुट बिहारी लाल : उसके बाद गैप होगा ।

श्री ए० बी० वाजपेयी : वह गैप की बात मैंने पहले कह दी । आप चाहे अलग अलग विदेशी सहायता और नये साधनों की व्यवस्था कहिये, जो तीन हजार करोड़ रु० है । इतनी राशि एकत्र करने का स्मृति-पत्र में हवाला दिया गया है । मैं गैप की चर्चा कर चुका । अब मैं दूसरी चर्चा कर रहा हूं । इस बात से सभी सहमत हैं कि इतने बड़े पैमाने पर यदि नये साधन जुटाने का यत्न होगा, तो उससे आर्थिक व्यवस्था पर तनाव बढ़ेगा । कहा जाता है कि भारत ऐसा देश है, जहां सब से अधिक टैक्स हैं । वित्त-मंत्री जी ने भी अपने भाषण में इसका उल्लेख किया है । स्मृति-पत्र में यह भी कहा गया है कि हम घाटे की अर्थव्यवस्था नहीं करेंगे लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि योजना आयोग या वित्त-मंत्रालय इस आश्वासन का पालन कर सकेंगे ।

सब से बड़ी कठिनाई इस लिये पैदा होती है कि हमने विकास के काल को खंडों में बांटने का यत्न किया है । विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है । उसे पांच वर्ष के काल-खंडों में बांटा जाये, यह न तो तर्कसंगत है और न यह उपयोगी है । शासन का सारा ध्यान इस बात की ओर रहता है कि हम पांच वर्ष के लिये लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य आंकड़ों में तय होते हैं और फिर उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये जुट जायें, भले ही उसके अनुरूप साधन न हों या उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये जिस तरह का संगठन जिस तरह का प्रशासन चाहिये, उसकी भी स्थापना न की जा सके ।

महोदया, मेरा सुझाव है कि पांच वर्ष के लिए विकास की योजनाएं बनाने के प्रश्न पर पुनर्विचार होना चाहिए । पांच वर्ष के साथ कोई पवित्रता जुड़ी हुई नहीं है । अभी भी हम ऐसे काम हाथ में लेते हैं जिनकी चरम परिणति पांच वर्ष के बाद होती है । अगर हम नियोजन के मोटे मोटे लक्ष्य तय कर दें, आधार-भूत नीतियां निर्दिष्ट कर दें, वरीयताएं, प्राय-रिटीज़, तय कर दें और जो ब्यौरे की चीजें हैं वह छोड़ दें तो हमारे नियोजन में एक प्रैगमेटिक एप्रोच आयेगा और उसके परिणाम अधिक फलदायी होंगे ।

वित्त-मंत्री महोदय ने यह भावना पैदा करने की कोशिश की है कि उन्होंने लोगों को राहत दी है । कुछ अर्थों में तो राहत दी है— उत्पादन-शुल्क में कमी की गई है, आयकर भी घट गया है, लेकिन राहत केवल 42.99 करोड़ रुपये की है और वित्त-मंत्री ने इस बात का अनुमान नहीं लगाया कि 17 फरवरी को बाहर से आने वाले माल के ऊपर उसके मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर जो रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई गई थी, उससे कितनी आमदनी होगी । महोदया, मैं समझता हूं कि यह तरीका गलत है कि बजट पेश करने के 10 दिन पहले इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देना, उससे कितनी आमदनी

होगी, इस सम्बन्ध में भी सदन को, देश को, विश्वास में न लेना और फिर 10 दिन बाद 27 फरवरी को आ कर यह माया जाल फैलाना कि हमने लोगों को राहत दी है और लोगों पर अधिक बोझा नहीं डाला । मैं समझता हूं कि वित्त-मंत्री महोदय स्पष्ट करेंगे कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से सरकार को कितनी आय होगी? मेरा अनुमान है कि कम से कम 100 करोड़ की आमदनी होगी । फिर हम यह भी नहीं भूल सकते कि कुछ दिन पहले रेल मंत्री ने 21 करोड़ रुपये का नया भार डाला है . .

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI T. T. KRISHNAMACHARI) : Will the hon. Member make a bargain? I will accept Rs. 70 crores from him.

SHRI A. B. VAJPAYEE: Madam, it is very difficult for me to bargain with the Finance Minister.

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): Rs. One Hundred crores must be based on some basis.

PROF. SATYAVRATA SIDDHANTALANKAR (Nominated): Let him come forward.

SHRI A. B. VAJPAYEE: Let the hon. Finance Minister give his own figures.

PROF. M. B. LAL: It is his duty to give us that information.

श्री ए० बी० वाजपेयी : महोदया, मेरी शिकायत है कि आमदनी कम आंकी जाती है और खर्चा बढ़ा कर बताया जाता है । इस साल के बजट में भी यह बात बिल्कुल साफ है । 1964–65 में रेवेन्यू सरप्लस 83 करोड़ आंका गया था लेकिन वह बढ़ कर हो गया 229 करोड़ और खर्च का भी जितना अनुमान किया गया था उससे 42 करोड़ रुपए कम खर्च हुए हैं । अब इतनी बचत हुई है और ध्यान में रखना होगा कि जब पिछले साल बजट पेश किया गया था तब वित्त-मंत्री को यह ख्याल नहीं था कि 38 करोड़ रुपया कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का और देना होगा, पुनर्वास पर खर्चा बढ़ेगा और राज्यों को भी अधिक सहायता हमें करनी पड़ेगी, ये नए खर्चे उठाने पड़ेंगे, किन्तु उसके बाद भी 104 करोड़ रुपए की बचत हुई ।

श्री बी० आर० भगत : 70 करोड़ रुपये की जो कमी की गई ?

श्री ए० बी० वाजपेयी : वह तो अभी की बात है, उस पर भी आगे आऊंगा ।

श्री बी० आर० भगत : नहीं, पहले की बात है ।

श्री ए० बी० वाजपेयी : मैं समझता हूं कि अगर आमदनी का सही अनुमान नहीं लगाया जायेगा तो फिर टैक्सों में कमी करने की जो और गुंजाइश थी, उस के साथ वित्त-मंत्री जी न्याय नहीं कर सकेंगे ।

जो आयकर में छूट दी गई है वह ऊंची श्रेणी के वर्ग को अधिक दी गई है और नीची श्रेणी के वर्ग को कम दी गई है । चीनी आक्रमण के बाद सन् 1962–63 में आयकर के ऊपर एडिशनल सरचार्ज लगा था । वित्त-मंत्री जी ने जो नई सुविधाएं दी हैं उनसे ऐसा लगता है कि जो अधिक आमदनी वाला वर्ग है उनको तो 5 फीसदी की छूट दो जायेगी, लेकिन साढ़े सात हजार और दस हजार के बीच का जो वर्ग है उसके लिए एडिशनल सरचार्ज एक प्रकार से स्थायी बन कर रह जायेगा । होना यह चाहिए था कि इस वर्ग को भी अधिक सुविधायें दी जातीं ।

उत्पादन-शुल्क में जो कमी की गई है, उसके लिए वित्त-मंत्री ने आशा प्रकट की है कि वह उपभोक्ता तक पहुंचेगा, लेकिन

[श्री ए० बी० वाजपेयी]

अभी जो बाजार का ढंग है उसमें वह उपभोक्ता तक पहुंचता हुआ दिखाई नहीं देता । वैसे भी उत्पादन-शुल्क जिस गति से बढ़ रहा है उसे देखते हुए उसमें और भी कमी करनी चाहिए थी । उत्पादन-शुल्क 1950–51 में 63·43 था और 1955–56 में 145 करोड़ और 1964–65 में 770 करोड़ रुपया हो गया । वित्त-मंत्री जी टैक्सों में और भी राहत दे सकते थे, क्योंकि तीसरी योजना के पांच वर्षों के लिए टैक्स से जितनी आमदनी का अनुमान लगाया गया था उसको देखते हुए तीन वर्ष में ही, या अगर हम चौथा वर्ष भी जोड़ लें तो यह राशि 2,550 करोड़ रुपये हो जाती है, जबकि अनुमान इसके आधे के बराबर था । आर्थिक नियोजन के 13 वर्षों में राष्ट्रीय आमदनी के साथ टैक्सों का जो अनुपात है, वह 6 फीसदी से बढ़ कर 14 फी सदी हो गया है । वित्त-मंत्री जी ने शहरी सम्पत्ति पर कर लगाने का प्रस्ताव रखा है । कुछ क्षेत्रों में उस प्रस्ताव को समाजवादी कह कर उसका स्वागत किया गया है । मैं नहीं समझता कि उसमें समाजवादी क्या है ? लेकिन उससे जो व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा होंगी उनको ध्यान में रखना चाहिए । रेलवे बजट में भी ऐसे माल के ढोने पर भाड़ा बढ़ाया गया है जिस का सम्बन्ध मकानों के निर्माण से है; जैसे चूना है, पत्थर है, लोहे की चीजें हैं जो कि मकान के बनाने में लगती हैं, उन्हें रेल मंत्री ने महंगा करने का यत्न किया है । वित्त-मंत्री जी विचार करें कि क्या शहरी सम्पत्ति पर कर लगाने का प्रस्ताव देश में मकानों के निर्माण का जो कार्यक्रम पहले ही काफ़ी धीमा चल रहा है, उसको और अधिक धीमा नहीं करेगा ?

महोदया, इस वर्ष हम ने मूल्यों में असाधारण वृद्धि देखी और आर्थिक समीक्षा में स्वीकार किया गया है कि 1963–64 में थोक मूल्यों में 9.1 परसेंट की वृद्धि हुई थी और जब कि 1964–65 में 14 परसेंट की वृद्धि हुई है । यदि हम आर्थिक नियोजन को सफल बनाना चाहते हैं तो मूल्यों को स्थिर रखने के लिए प्रभावी पग उठाने होंगे । मूल्यों को स्थिर रखने की कुंजी खेती में है; क्योंकि खेती न केवल हमारे औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल देती है, बल्कि हमारी जनसंख्या के 50 फीसदी खर्चे को भी—जो कि भोजन के ऊपर होता है—वह पूरा करती है । लेकिन खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्यों के अनुसार नहीं हो रहा । यद्यपि कुछ दिनों से स्थिति सुधरने के आसार दिखाई दे रहे हैं; तथापि मैं सरकार को चेतावनी देना चाहूंगा कि खाद्य के मोर्चे पर वह यह अनुभव करने की गल्ती न करे कि संकट टल गया है । यह ठीक है कि गेहूं की फसल अच्छी है, मूल्यों में कुछ कमी हो रही है, लेकिन जून में, जुलाई में बरसात में परिस्थिति फिर से विषम हो सकती है । किसान अब अपनी जरूरत से ज्यादा अधिक अनाज अपने पास रखना चाहता है । सरकार को खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई ठोस योजना बनानी होगी; क्योंकि अगर हम अनाज के दामों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, तो फिर जो कम आय वाले वर्ग के लोग हैं वे निश्चय ही संकट में पड़ जायेंगे ।

महोदया, यह सुझाव दिया गया है कि एक नेशनल प्राइस स्टैबिलाइजेशन बोर्ड बनना चाहिए जो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हितों को ध्यान में रख कर मूल्यों का निर्धारण करे । अभी फूड कारपोरेशन है, टैरिफ कमीशन भी है, कर्मचारियों के लिये भिन्न-भिन्न वेज बोर्ड भी बनते हैं, लेकिन हम मूल्यों की समस्या पर टुकड़ों में विचार करते हैं । अगर इस समस्या पर सम्यक विचार करना है तो नेशनल प्राइस स्टेबिलाइजेशन बोर्ड की स्थापना के सुझाव पर वित्त-मंत्री को गंभीरता के साथ सोचना चाहिये ।

SHRI AKBAR ALI KHAN: There is a Commission appointed under Prof. Daruwala to look into this matter.

SHRI A. B. VAJPAYEE: Only agricultural prices. It has nothing to do with industrial prices and wages. I want the whole problem in its various aspects to be taken into consideration.

महोदया, चौथी पंचवर्षीय योजना का जो स्मृति-पत्र है, उसमें यह कहा गया है कि जो सरकारी कल-कारखाने चल रहे हैं उनमें अगर 12 फी सदी का मुनाफा हो तो यह संतोषजनक है । मैं नहीं जानता, यह 12 फीसदी की रकम, यह मुनाफे की दर, किस आधार पर तय की गई है ? लेकिन आडिट रिपोर्ट ने जो तथ्य सामने रखे हैं उससे पता लगता है कि हमारे सरकारी कल-कारखाने 12 फी सदी से कहीं अधिक लाभ कर रहे हैं । अगर पब्लिक सेक्टर के कल-कारखाने लाभ या अधिक लाभ करते हैं तो उसका स्वागत होना चाहिये, लेकिन लाभ इस तरह की मूल्य नीति निर्धारित करके न हों कि उसमें एलीमेन्ट आफ टैक्सेशन कर का तत्व आ जाये । उदाहरण के लिये स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन है । उसने 51 फीसदी से अधिक मुनाफा किया है । मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं है । लकिन जिस दर पर वह फर्टिलाइजर्स बाहर से ला रहा है और जिस दर पर हमारे किसानों को बेच रहा है, वह जरूर आपत्तिजनक चीज़ है । जब स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने रासायनिक खाद का आयात और उसका वितरण अपने हाथ में लिया तब यह कहा गया था कि यह "नो लास नो प्राफिट बेसिस" पर किया जायेगा, लेकिन अब मुनाफाखोरी हो रही है—मैं इसे कोई और दूसरा नाम नहीं दे सकता । मेरे पास आंकड़े हैं जो आडिट रिपोर्ट (कार्मशियल) में दिये गये हैं । उनसे पता चलता है कि प्रति मीट्रिक टन पर अब 300 रु० से अधिक, फर्टिलाइजर्स के ऊपर, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन मुनाफा कर रहा है ।

SHRI C. M. POONACHA (Mysore): May I, by way of explanation, inform the hon. Member that it is not so? I have personal knowledge about the working of the S.T.C. The S.T.C. acts as an agent to the Food Ministry and the disposal of the fertilizers so imported is entirely in the hands of the Food Ministry, while the S.T.C. is paid a nominal commission to meet out-of-pocket expenses.

श्री ए० बी० वाजपेयी : महोदया, मैंने हवाला दिया . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: Will you take another ten minutes?

श्री ए० बी० वाजपेयी : मैं जरा खत्म कर लूं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House will sit till 1.30.

श्री ए० बी० वाजपेयी : यह जो मैंने हवाला दिया, यह सन् 1964–65 की आडिट रिपोर्ट (कार्मशियल) है और माननीय सदस्य उसको देखने का प्रयत्न करें । यह कहना काफी नहीं है कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन मुनाफा नहीं कर रहा है और फूड एन्ड अग्रिकल्चर विभाग मुनाफा कर रहा है । देखना यह है कि किसान को किस दर पर फर्टिलाइजर दिया जाता है, और अगर कहीं मुनाफा हो रहा है तो किसान की कीमत पर हो रहा है और अनाज की पैदावार बढ़ाने की योजना को खटाई में डाल कर हो रहा है । कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे सार्वजनिक उद्योग घाटे में चलें—उन्हें मुनाफा कमाना चाहिये । लेकिन, मुनाफा आम आदमी की, कन्ज्यूमर की, कीमत पर नहीं होना चाहिये ।

महोदया, हमारे वित्त-मंत्री विदेश पूंजी के लिये भारत का द्वार चौड़ा खोलते जा रहे हैं । मैं विदेशी पूंजी के खिलाफ

[श्री ए० बी० वाजपेयी]

नहीं हूं, अगर वह हमारी शर्तों पर आती है और उससे भारत को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने में मदद मिलती है । लेकिन जिस ढंग से नीतियां अपनायी जा रही हैं उससे आशंका पैदा होती है कि कहीं ऐसा न हो कि विदेशी पूंजी के लिये हम इतना द्वार खोल दें कि उस द्वार से हमारी स्वाधीनता, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति और आर्थिक दृष्टि से भारत को स्वावलम्बी बनाने के लिये हमारा महान् लक्ष्य, ये भी बाहर निकल जायें । प्राचीन काल में हम एक अनुभव देख चुके हैं, जब तराजू की डंडी को राजदंड में बदला गया था । राजनैतिक पराधीनता का उस अर्थ में ख़तरा हमारे सामने नहीं है । लेकिन विदेशी पूंजी विदेशी प्रभाव को बढ़ाती है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । मुझे आश्चर्य है, विदेशी पूंजी को ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं जो देशी पूंजी को भी प्राप्त नहीं हैं । यह कहना भी कठिन है कि विदेशी पूंजीपति सचमुच में भारत का आर्थिक या औद्योगिक विकास चाहते हैं । उनके सामने प्रमुख लक्ष्य मुनाफा कमाने का है और इसीलिये अपने आधारभूत (बेसिक) उद्योगों को विकसित करने के लिये जितनी पूंजी हमें चाहिये, वह विदेशों से नहीं मिल रही है । ब्रिटेन और अमेरिका के हमारे सहयोगी हमें गेहूं देने के लिये तैयार हैं, मगर स्टील प्लान्ट देने के लिये तैयार नहीं हैं । ऐसे उद्योग जिनमें हम अपनी मशीनें तैयार करें, आर्थिक विकास की नींव रख सकें, उनको जिस मात्रा में विदेशी पूंजी को आकृष्ट करना चाहिये, वह नहीं कर पा रहे हैं । अधिकतर विदेशी पूंजी उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन में लग रही है । सारा मुनाफा बाहर जाता है, विदेशी मुद्रा के रूप में, जो उसी अनुपात में हमारे आर्थिक विकास की गति को रुद्ध करता है ।

सरकार पेटेन्ट लॉ में संशोधन करने जा रही है । उसका रूप क्या होगा, यह हम जानना चाहेंगे । एक बात हम न भूलें कि भारत में अभी तक जितने भी पेटेन्ट्स रजिस्टर्ड हुए हैं उनमें 90 फीसदी विदेशी हैं । वे हमारी कम्पनियों के साथ समझौता करते हैं कि उसमें शर्त लगाते हैं कि उनका जो टेकनीक है, उनकी जो विधि है, उसे गुप्त रखा जायेगा । एन्टी बायोटिक्स में हम ने एक विदेशी फर्म के साथ समझौता किया और उसमें भी उन्होंने इसी तरह की शर्त लगाई । हमें कच्ची फिल्म बनाने के लिये एक विदेशी फर्म से सरकारी समझौता करना था तो उसे यह भी आश्वासन दिया गया कि उस फर्म के 40 ऊंचे पद वह विदेशियों को दे दें । मगर वह कम्पनी आई नहीं । आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि नये कल-कारखानों के लिये लाइसेन्स देने की प्रणाली बदली जायेगी और गैर-सरकारी विदेशी निवेशकों को जो भारत में भारतीय भागीदारों के साथ सहयोग करके पूंजी लगाना चाहते हैं, स्वीकृति-पत्र (लेटर आफ इन्टेन्ट) जारी किया जायेगा । नीति परिवर्तन हमारे देश की छोटी और मध्यम पूंजी वालों के खिलाफ जायेगा । अभी तक सरकार भारतीयों को लाइसेन्स देती थी और फिर वे इस बात का प्रयत्न करते थे कि विदेशी पूंजीपतियों के साथ गठबंधन कर सकें । अब सीधे लाइसेन्स विदेशी पूंजीपतियों को दिये जायेंगे, जिसका नतीजा यह होगा कि वे भारत में आकर इस बात का पता लगायेंगे कि किस पक्ष के साथ, किस पार्टी के साथ, गठबंधन करें और इसमें जो बड़े बड़े धन कुबेर हैं, जो हमारे देश में अट्ठारह बीस परिवार हैं, जो सारी अर्थ-व्यवस्था पर हावी हो गये हैं और आर्थिक नियोजन के परिणामस्वरूप जिन्होंने दौलत के अंबार खड़े किये हैं, उनको लाभ होगा, छोटे और मध्यम श्रेणी के पूंजीपति को, उद्योगपति को, नहीं । मैं समझता हूं, सरकार की नीति आर्थिक शक्ति और आर्थिक सम्पत्ति का एकत्रीकरण रोकने की है । किन्तु लाइसेन्स देने की

पद्धति में जो नया परिवर्तन किया जा रहा है वह इस नीति के खिलाफ जाता है।

महोदया, सन् 1946 से 1961 तक देश में अमरीकी पूंजी 11 करोड़ से बढ़ कर 96 करोड़ हो गई। सन् 1957 में विदेशी कम्पनियों के साथ देश में 81 गठबंधन, (कोलोबोरेशन) हुए थे जिनमें अमरीकन गठबंधन केवल 6 थे। सन् 1964 में अमरीकन गठबंधन की संख्या 78 हो गई। ब्रिटिश पूंजी बड़ी तीव्र गति से हमारे देश में बढ़ रही है। 1948 में 226 करोड़ ब्रिटिश पूंजी थी और 1961 में 447 करोड़ हो गई। सन् 1964 में ब्रिटिश फर्मों के साथ 105 गठबंधन के समझौते हुए। मैं इन आंकड़ों से कोई गलत अर्थ नहीं निकालना चाहता हूं, लेकिन विदेशी पूंजी निमंत्रित करते समय हमें सावधानी से काम लेना होगा। आस्ट्रेलिया के एक अर्थशास्त्री हैं, शायद वित्त-मंत्री जी ने उनका लेख पढ़ा होगा। उन्होंने एक नोट प्लानिंग कमीशन को भेजा है। उनका नाम श्री इ० एल० ह्वील राइट है और उन्होंने भारत सरकार को यह चेतावनी दी है। वे कम्यूनिस्ट नहीं हैं, वे भारत का अहित चाहने वाले भी नहीं हैं। श्री इ० एल० ह्वील राइट का कहना है कि विदेशी पूंजीपति 5 साल में मुनाफा कमा कर के अपनी सम्पत्ति वापस ले जाना चाहते हैं। अगर यह बात सच है तो विकास की कोई भी दूरगामी योजना विदेशी पूंजी पर निर्भर रह कर फलीभूत नहीं हो सकती है। हमें विदेशी पूंजी का उपयोग करना चाहिये लेकिन विदेशी पूंजी कोका कोला के रास्ते न आये, भारी उद्योग के रास्ते से आये तो उसका विचार किया जा सकता है।

महोदया, मैं एक मुद्दा कह कर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। मैंने अधिक समय ले लिया है, इसके लिए मैं आप से क्षमा चाहता हूं। वित्त-मंत्री महोदय, जो अनएकाउन्टेड मनी, बेहिसाब आमदनी या सम्पत्ति है, उसका पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप कितनी आमदनी होगी, उसका भी उन्होंने अनुमान नहीं लगाया है। क्या वित्त-मंत्री महोदय यह समझते हैं कि इन छापों का अधिक परिणाम नहीं होगा और इस तरह से अधिक मात्रा में धनराशि नहीं पकड़ी जायेगी? फिर भी जितनी धनराशि अभी तक प्राप्त हो चुकी है, उसका बजट में हिसाब लगाया जाना चाहिये था और जितनी धनराशि प्राप्त करना चाहते हैं, आशा करते हैं, उसका भी बजट में संकेत देना चाहिये था। मगर वित्त-मंत्री जी इस बात पर मौन धारण किये हुए हैं। उनका मौन उनके भाषण से भी अधिक मुखर हो सकता है, किन्तु उसका अर्थ हम अपनी दृष्टि से लगायेंगे। यह स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिये कि छापे के द्वारा जितनी भी बिना हिसाब की सम्पत्ति है, आमदनी है, उसका पता लगाया जायेगा। अगर स्वेच्छा से लोग अपनी बेहिसाब सम्पत्ति घोषित कर रहे हैं, तो यह ठीक है। लेकिन 60 फीसदी जमा करके और 40 फीसदी में संतोष करके अधिक लोग अपना बेहिसाब धन बतायेंगे, ऐसी मुझे आशा नहीं है। फिर यह जो 60 और 40 फी सदी का अनुपात है वह केवल बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों पर लागू होता है, छोटे और मध्य श्रेणी के पूंजीपतियों पर टैक्स की यह दर नहीं है। क्या वित्त-मंत्री जी जो छोटे और मध्य वर्ग के पूंजीपति हैं, जिनके पास भी बेहिसाब धन हो सकता है, वे भी 60 फीसदी धन जमा करके 40 फीसदी में संतोष करेंगे, यह अनुमान लगाना चाहते हैं? अगर यह अनुमान लगाना चाहेंगे तो छोटे और मध्य श्रेणी के पूंजीपतियों को अपना धन घोषित करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी, इस बात पर वित्त-मंत्री जी को विचार करना चाहिये? अभी तक कुल 35 करोड़ रुपया छापों से प्राप्त हुआ है,

[श्री ए० बी० वाजपेयी]

जबकि काले धन का अनुमान 1,500 करोड़ रुपया और 20 हजार करोड़ रुपया लगाया गया है । हम लोग जानना चाहेंगे कि बाकी धन को निकालने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं । वित्त-मंत्री जी ने अपने भाषण में माना है कि बेहिसाब धन जो इकट्ठा होता है, वह करों की चोरी करके इकट्ठा होता है या मूल्यों के सम्बन्ध में जो नियम बने हुए हैं, उनका उल्लंघन करने से इकट्ठा होता है । उन्हें इस बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि क्या टैक्सों में ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे टैक्सों की चोरी करने का जो लोभ है, वह कम हो जाये । अगर ईमानदारी से कोई आदमी सारे टैक्स जमा कर दे तो उसका अपना खर्चा चलना सम्भव नहीं है और इस तरह से वह चोरी करने के लिए प्रेरित होता है और पुलिस के छापे इस प्रवृत्ति को नहीं रोक सकेंगे । वैसे जो छापे मारे गये हैं वे छोटे छोटे लोगों पर मारे गये हैं और बड़े बड़े लोग अभी तक छापों से बचे हुए हैं । सरकार ऐसा जाल फैलाती है कि छोटी छोटी मछलियां तो फंस जाती हैं, मगर बड़े बड़े मगरमच्छ निकल जाते हैं ।

महोदया, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जिन विवाहित व्यक्तियों के दो बच्चे हैं, जिनकी आमदनी 5 हजार रुपये तक है, उनसे इन्कम टैक्स न लेने के सवाल पर वित्त-मंत्री जी को गम्भीरता से विचार करना चाहिये । इससे केवल 2 करोड़ रुपये का घाटा होगा, लेकिन 5 लाख लोग आय कर से बरी हो जायेंगे । आय कर देने वालों की संख्या कुल 14 लाख है इसके साथ ही कम्पनियों पर कर की जो व्यवस्था है वह 60 फीसदी है । यदि हम चाहते हैं कि पूंजी इकट्ठी हो, उद्योगधन्धों में लगे, हमारी विकास की गति बढ़े, देश में समृद्धि आये और समानतर वितरण हो तथा हर एक आदमी सुखी रहे, तो पूंजी निवेश को बढ़ाना होगा । सात महीने पहले कम्पनी टैक्स 25 फीसदी था और अब 60 फीसदी हो गया है । क्या वित्त-मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि यह 50 फीसदी किया जा सकता है ?

एक बात मैं ब्रह्मचारियों के बारे में कह कर खत्म कर दूंगा । ब्रह्मचारियों से मेरा मतलब बैचलरों से है और अगर आप चाहें तो उन्हें अविवाहित कह सकते हैं । एक ओर तो सरकार परिवार नियोजन की बात करती है, परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देना चाहती है, लेकिन दूसरी ओर बैचलरों, ब्रह्मचारियों, को अधिक टैक्स देना पड़ता है । अभी जो इन्कमटैक्स कानून में संशोधन किया गया है . . .

श्री महाबीर प्रसाद भार्गव (उत्तर प्रदेश) : उनका खर्च कम होता है ।

श्री ए० बी० वाजपेयी : उनका खर्च कम नहीं होता है, खर्च करने वाली घर में नहीं रहती, तो खर्च ज्यादा होता है ।

श्री महाबीर प्रसाद भार्गव : अगर आप ने समझ लिया है, तो ले आइये ।

श्री ए० बी० वाजपेयी : लेकिन मैं परिवार नियोजन में हिस्सा बटाना चाहता हूं । मेरा निवेदन है कि बैचलरों के बारे में जो इन्कम टैक्स का मसला है, उस पर वित्त-मंत्री जी जरा सहानुभूति से विचार करेंगे । जब फाइनेन्स बिल आयेगा तो मैं इस सम्बन्ध में ठोस बात कहूंगा, लेकिन हम उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, यह बात हमें समझनी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि वित्त-मंत्री महोदय ने जिस तरह का बजट पेश किया है, जो उन्होंने आशा लगाई है, उस आशा के अनुपात में नई दिशा में संशोधन करेंगे, ताकि हमारे विकास की गति और तेजी से बढ़ेगी जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे ।

SHRI C. M. POONACHA: Madam, I wholeheartedly welcome the Budget proposals presented by the Finance Minister for the consideration of Parliament and I also congratulate him for having conceded the much needed relief to certain classes of taxpayers. The Budget, in my view, is a sound Budget, a preparatory Budget for the coming Fourth Five Year Plan and it also happily provides a good augury for the ushering in of the Fourth Plan. It has for the first time set the thinking in the direction of avoiding the concentration' of our energies in the urban areas and trying to give a shift for the active energies towards our rural areas. In these respects, I find that the Budget has been very ably and considerably prepared with sufficient care to collect the much needed revenues for the Government, to meet the various commitments the Government has to undertake.

However, on one point I have my own views about the Budget and that is, as in the past, this Budget also lacks the appreciation that is needed for stepping up of the agricultural production in the country. As far as agriculture is concerned, I am afraid, Madam, this Budget does not provide for sufficient relief. Nor does it indicate in precise terms a bold and vigorous policy to step up agricultural production in this country. Rightly or wrongly, that has been the course of events right during the First Five Year Plan, the Second Five Year Plan and the Third Five Year Plan, programmes. In these programmes agriculture did not get the deserved attention, while more attention was paid to big industries and to projects which take a great deal of time to bring results. Thereby agriculture generally has not progressed to the extent we desired.

I attempted to scan through some of the figures and to my surprise I found that as for agriculture, the First Five 'Year Plan provided about 14-8 per cent of the total outlay and in the Second Plan, the allocation was much less, namely only 11-3 per cent of the total outlay. In the Third Plan, it was 13-3 per cent. In the Fourth Plan, according to the indications already provided, it Is estimated that the allocation for agriculture will be about 15-4 per cent. And here too, agriculture means what? Agriculture would include, agriculture, forests, cooperation, community development, animal husbandry, etc. For all these nation-building activities which are grouped under the major head "Agriculture" the allocation has been rather meagre even in this Budget which is in a way the forerunner for the ushering in of the Fourth Plan. After having had the experience of serious difficulties with regard to the availability of foodgrains in this country, the needed emphasis on agricultural production is not found in the Budget which has been presented to the House. During the previous years, as I was trying to explain, more than 70 per cent of the Plan outlay went to the non-agricultural sectors. Agriculture having been left to its own fate, a stage has now been reached when the country can only look forward to survival if the agricultural production in this country Is stepped up and a vigorous, may I say an aggressive policy, is adopted in this direction. Whenever discussions take place over the Budget whether here in Parliament or elsewhere, particularly in the Press, we oftentimes hear that the "climate" for investment, the "climate" for saving and the "climate" for capital formation, is not created. There is so much discussion about this "climate", while everybody seems to think that for agriculture no "climate" is necessary. Probably mother Nature provides the climate for agriculture and there too the vagaries of nature are well known and still everybody seems to be somewhat content. This, in my view, is the greatest shortcoming as far as the Budget that is presented before the House is concerned. The agricultural produce, as was mentioned by the earlier speaker, forms the basis from which we get the raw materials for our industries and they also form the mainstay of our traditional exports. That being so, the attention that agriculture has received in the proposals that the Finance Minister has so ably put before us is rather halty. While the various impositions and levies by way of excise duties and such other impositions do continue, let alone any

[Shri C. M. Poonacha.]

thinking in the direction of developments, there is not even the slightest indication of providing a little relief in the matter of the various excise and other taxes that are levied on agricultural production, particularly the plantation production. The tea industry, coffee industry, the rubber industry, jute and various other things have not come up for the consideration of the Finance Minister in the matter of providing any relief. The various levies have been taken up to the highest level and left where they are. There they will continue while reliefs are considered for other sectors, non-agricultural sectors, but not for the agricultural sector. This is my complaint against the Budget that is before the House for consideration. As for planta-1 P.M. tion industry, if I may take this opportunity to mention a few words, he has had some consideration no doubt for tea; but it is a very very poor relief that is attempted to be given by way of some rebate on development in respect of new cultivation as well as old plantations. But that does not take the industry far. The Committee that was constituted to go into the working of the tea industry, the Tea Finance Committee, had gone into the various aspects of the tea industry. This is one of our biggest plantation industries which provides opportunities for us to earn substantial amount of foreign exchange. The Committee's Report has not been given any consideration except in this matter of a small concession that has been granted. So also the coffee industry. The costs of all conceivable items that are needed in the course of development of the plantation industry are steadily going up. With the regulatory increase of import duty introduced by the Finance Minister a few days ago the cost of the much needed materials for the plantation industry has gone up. Transport costs have gone up; the costs of steel and other items have gone up. The fertiliser cost has gone up; not only that, fertilisers are not even available in sufficient quantities with the result that the cost of production is steadily going up year after year but the excise duties and such other levies are at their very high levels without any sort of modification to the advantage of the plantation industry. It is in this context we fondly hope that the agricultural produce should increase and our country should be strong with an agricultural bias and we look forward to solving our food problem. In the thinking at the Centre and in the Finance Ministry, there is no such thing as providing incentives to agricultural production at all. This is a thing which has to-be looked into by the Finance Minister and I am sure that before he comes to his final decision he would certainly look into the case of the plantation industry and agriculture in general and provide the necessary relief and necessary incentives required in this direction.

Now, take the situation that has been created after the presentation of their Budgets by the various State Governments. The Central Budget with the great ingenuity of the Finance Minister has. been made to appear a balanced one while the State Budgets, as they are presented, are all deficit Budgets with huge gaps. Except the State of Assam and the State of Punjab, all the other State Governments have come forward with deficit Budgets of Rs. 4, Rs. 6, Rs. 8 or Rs. 10 crores and so on and the total deficit comes to about Rs. 60 crores. And I think none of them is covered except perhaps the Rajasthan Government which has attempted to cover a small portion of the gap. So what is the position? We have a huge cumulative gap—of all the State Budgets put together—of more than Rs. 60 crores and here at the Centre we have a balanced Budget and the Finance Minister assuringly has given us his promise that there would not be any resort to deficit financing. What is then going to happen ? Either the State Governments should think of fresh taxation, fresh levies and try to bridge the gaps or they must come to the Centre and ask for assistance from the Centre. If they are to resort to the first method, the field left open to the State Governments to collect taxes being very inelastic, the only proposal by the State Governments could be to tax the agriculturists; nothing beyond that. That is the only thing that is left open to them. If that is done, surely and definitely it is going to retard agricultural production. It will not create a conducive climate for agricultural production to be

stepped up and so it will be a sort of boomerang which will hit us in return and create more food crisis and food scarcity in the country.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over.

SHRI C. M. POONACHA: Yes, Madam. Suppose the other method is resorted to by the States and they all join and come to the Centre for assis-*" tance, the nice plan of the Finance Minister will be completely up-set and his Budget will never be a balanced one in the event of his trying to assist the various State Governments to cover their budgetary gaps. So this is the overall picture of our financial affairs and one is not enthused to see how the financial framework of the country—the Centre and the States put together—appears. The Finance Minister has no doubt said in his speech that he would summon all the Finance Ministers of the States and hold consultations with them. He is himself concerned about this aspect and there is a passing reference in his speech to this no doubt. I would suggest that he should take abundant care that the State Governments in their hurry to cover their budgetary gaps which they have left uncovered do not touch the agricultural sector, do not come forward with fresh imposts, fresh levies or fresh taxation that might burden the lot of the agriculturists. Unless that care is taken, unless that is ensured, the strain on the overall economy of the country as a result of import of foodgrains will continue for a very very long time and the much needed stepping up of food production will not materialise. I therefore request the Finance Minister to bestow his careful attention upon this aspect of the question and see while balancing his own Budget that he takes into consideration the Budget position of the various State Governments and helps them to carry on their programmes of development. At the same time, he should see that from the Centre as well as from the States, the necessary incentives, the necessary reliefs, the necessary encouragement for production of foodgrains and other agricultural produce, are ensured.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please wind up. You have taken nearly 20 minutes.

SHR C. M. POONACHA: With these words, Madam, I support the Budget and welcome it. And I hope that before the final picture is drawn up by the Finance Minister the various points mentioned in the House and the reference particularly to agricultural production will be borne in mind and necessary action taken. Thank you.

SHRI B. K. GAIKWAD (Maharashtra): Madam Deputy Chairman, while speaking on the Budget I must show my satisfaction, as the Government have not imposed any tax, as was being done every year in the past. I will have my observations on the Budget on certain points, whether the Budget will really help the common man in the country in getting the real necessities of life such as food, clothing and shelter. As far as the food problem is concerned, you will find that the country is facing a great scarcity for the[1] last several years. So, I need not mention it in detail. Every year the Government is importing foodstuffs from outside countries. Even then people are facing great difficulties in getting foodstuffs for their maintenance. If that is the position, the question is whether it is possible and feasible for the Government to grow more food in this country. You will find that there is considerable Government wasteland available where foodstuffs can be grown. As far as my knowledge goes, I think the land which is available for cultivation with the Government is about 8 crores of acres. This land is available with the Government. If this land is given to the landless people for cultivation, they will cultivate the land and they will grow more food which is the first necessity of our country. In spite of all that you will find that such lands are not given to the people for cultivation. What is the hitch, what is the difficulty in not giving such land for cultivation? You will find people are there for cultivating the land. The land is there. What is the difficulty? The difficulty is that in every village you will find that there are land-| lords. These landlords want labourers

[Shri B. K. Gaikwad.]

working under them at a very cheap rate and if these lands are given to the landless people for cultivation, then, these landlords will not get cheap labour at their disposal. So, whenever land is demanded by a landless man for agriculture, whether the application is addressed to the Prime Minister or to the Governor or to the President, or whatever officer there may be in the country, naturally it goes to a Patwari. In Maharashtra we call the Patwari or Patil and "Thalatti" and circle officer. When they go to investigate in the village naturally they go and stay with the rich man in the village, that is, the landlord who makes all arrangements for such officers. They go and sit there, discuss the matter, investigate the application and then the landlords show a desire that such land should not be given for cultivation to these landless people. Why? The reason is this. Suppose, these lands are given to the landless people who are working in their fields at a very cheap rate, whenever they want. These people, if they get such land, will not go and work in their fields. Naturally when the landlord shows his desire against giving such land to the landless people for cultivation, then you will find that the officer also submits a report against the persons who demand such land for cultivation. The reply that the landless people get is that their applications are rejected. That is the position. I just want to draw the attention of the Government to this, whether this fact is not known to the Government. You will find that this fact is also known to the Government, but the Government has also become helpless. Why? The reason is very simple. They always keep an eye on the coming elections. In the elections these landlords who are living in the villages are, what you call, the vote-getting persons, they are important persons. So, the Government does not want to displease such persons and the representative of the constituency does not want to dissatisfy them. So, in order to satisfy the landlord living in the village, in order that he should give you votes next time in the elections, the applications are rejected totally.

SHRI AKBAR ALI KHAN: But more votes are with landless labourers.

SHRI B. K. GAIKWAD: Yes, landless labourers are there in the villages, but they are under the pressure and thumb of these landlords. I do not know whether my hon. friend knows this or not.

SHRI AKBAR ALI KHAN: There was a time when they were under their thumbs.

SHRI B. K. GAIKWAD: Even today it is so. You will find that at the time of elections though a big number of voters are from landless and small agriculturists, even then, capitalist persons are elected. Why? Only because of their money, on account of their power, on account of their pressure, on account of their gooduism, which he is going to do at the time of elections. So, my hon. friend, Mr. Akbar Ali Khan, knows it very well. Even then if he wants this information, he should take it. Such is the position as far as the land problem is concerned. So, I request the Government to consider this matter very seriously and see that whenever such lands are demanded by landless people they are granted to them for cultivation. They should encourage the grow-more-food. campaign and should remove the scarcity which the country faces so that the food problem may be solved to a certain extent.

Then, the other problem you will find is that of unemployment in the country. The number of unemployed is increasing every year. What can be done in order to remove unemployment? My proposal is that if the land which is available with the Government is given to the landless people or to the unemployed people, then naturally to-a certain extent the unemployment problem will also be solved. What is the number? As I told you just now the land available is something like 8 crores of acres. If each landless man or unemployed person is given 8 acres per family, that will solve the problem of about four to five crores of people. In each family there will be the husband and wife and two or three children. If you calculate it, it comes to something like 4 to 5 crores. So, to a certain extent that problem will also be solved.

The third problem which the Government is facing seriously in this country is about the hutment-dwellers. Those who

are coming to the cities to earn their livelihood, to earn their bread, are from the villages. Why do they come here to the cities? They come here to the cities in order to earn their bread. When they come here to the cities, naturally they do not get any accommodation. They have no money to pay rent for a house. So, whatever land is available, lying idle or vacant, has been occupied by the people who come from the villages. They just erect their huts and after erecting their huts, whether permission is obtained from the Government or not, it is immaterial I call it. But even after submitting their applications for getting land for their huts, the applications are not considered for years together and many times they are rejected. In spite of all that, the persons who come to earn their livelihood in cities erect their huts just by the side of latrines, by the side of gutters which are full of dirty water. They erect their huts in such places. Now, you will find that in every big city such hutment-dwellers are in lakhs. You might have heard that a countrywide civil disobedience movement was started by the Republican Party of India in which there was one demand, namely, the hutment-dwellers should not be evicted from their huts unless and until they are provided with alternative accommodation. If no accommodation is available, at least alternative site should be given. And I am glad to tell you that our Prime Minister, the Home Minister and the Defence Minister were there at the time of settlement. All of them agreed that unless and until alternative, not accommodation, but site was given to these people who were occupying such huts up to the year 1962, they would not be evicted from their places. In spite of all that, what do we find today? Madam, here is the paper, "Patriot" dated Sunday, March 14, 1965. Here you find that a man dies as jhuggis are demolished. There was one person, Manphool, who was living in a hut. When his hut was to be demolished, of course he requested the police not to demolish it. I hear that he was severely beaten and due to that beating he died on the spot, on the very day. To that effect this report has been published in the "Patriot". The "Patriot" says that a 50 year old sweeper died on Saturday while his jhuggi was being pulled down by the demolition squad on Lower Bela Road in. the Jamuna Bazar area. There were so* many witnesses too to this. In spite of all that, when the dead body was sent to the hospital for post-mortem, I heard that it has been said that he died due to heart attack. I do not know what heart attack he received. But this is the position which is prevailing in the country today. This happened where? Right before the very nose of the Prime Minister, here in the capital, Delhi. This is not one solitary instance. Everywhere you will find that Government has started demolishing their huts without providing them any alternative site, which is great injustice in my opinion, which is a breach of the promise which has been given by the Government that they will not demolish the huts unless and until alternative site is given. That is a breach of the promise which was given by the Government. I request Government to consider the promises and act accordingly. In case they do not act according to the promises given, naturally they will have to face the consequences hereafter, because people will tolerate to a certain extent; everything has some limit, but this cannot go on to an unlimited extent. I would request this much that Government would consider this problem very seriously and act according to the promise given. Promise has been given that those who have occupied the site by 1962, their huts will not be demolished. So, this problem is there.

As I was urging this point, if lands are given to the people, we will be solving not only one problem but three problems. One problem is growing more food in the country. The second problem is removing unemployment. The third problem is this: people who are coming from villages to cities and living in jhuggis and jhopris— that problem also, I think, not to a certain extent but to a big extent will be solved because if people get land in villages, they will not come to cities and live just by the side of latrines or by the side of the gutter carrying dirty water. They will stay it* their villages. So, this problem should be considered by • the Government very seriously.

[Shri B. K. Gaikwad.]

Then, Madam, Government has a very bad habit. You will always find, whether people demand right things or wrong things, they will never consider it and decide once and for all. You will find that there is one problem of Goa merging with Maharashtra. In the last elections, you will find that the people who were elected in Goa were in favour of merger with Maharashtra. The Goa Assembly has also passed a resolution, requesting the Central Government to merge Goa with Maharashtra. But Government is always putting it off till tomorrow. I do not know the reason why they do it. The same case was there with regard to Maharashtra and Gujarat. It was a bilingual State. The Maharashtra people tried their level best, requested, passed resolutions, they did • everything they could, whatever it was possible, but nothing was done. Then they started an agitation in which hundreds of people were killed when our Mr. Morarji Desai was the Chief Minister under the Congress Government. When in the election, particularly in western Maharashtra, almost all Congress friends were defeated then they opened their eyes and they decided that there might be a separate Maharashtra. *(Interruption),* The same is the case here also. I request that Goa should be merged with Maharashtra as demanded by the Goanese people themselves, by the Goa Government. So that is also my request. Government should consider it very earnestly and should see that that is done.

SHRI GOPIKRISHNA VIJAIVARGIYA (Madhya Pradesh): I am not against the merger of Goa with Maharashtra. But we have waited for four centuries. Can we •not wait for five or six years?

SHRI C. M. POONACHA: Does not the hon. Member know that there is a very strong public opinion against the merger of Goa with any other neighbouring State? Is he not aware of this fact?

Simr B. K. GAIKWAD: Two hon. Mem-'bers have put me two questions. One question is whether we cannot wait for four or five years. I fail to understand what is the reason for which they want four or five years more, because I feel Government should take a decision as early as possible.

SHRI AKBAR ALI KHAN: An amicable settlement is always better.

SHRI B. K. GAIKWAD: My other hon. friend says that there is also opposition to this demand. I know there is an opposition no this demand, but it has already been decided by the people themselves at the time of the elections, and the elections were fought on this issue. Even after contesting the elections on this issue if a decision has been given by the people themselves, what rir<ht have we to say that there is also •opposition to this demand? Whether there is opposition or no opposition, if people are supporting this, a big majority of the people, you should concede it. You call it democracy. What kind of democracy is it? Many times it is said, whatever votes they get, that they are not majority in number. *(Time bell rings)* I will just refer to one or two points and finish.

In Delhi there is one Arjunnagar situated in the Humayunpur area. Some Scheduled C'*ste people who have come from Pakistan have purchased lands and constructed their own houses and are staying there for the last six or seven years. Our Government with the help of the Delhi "Development Authority came forward and had started acquiring the whole locality. For what? Government will demolish these houses and build its own houses and will sell them in public auction. Who will purchase these houses? Monied people, rich people, will go to the auction and will purchase these houses. I fail to understand what sort of business the Government has started. It is not a *bania* shop. What business does Government have to acquire the houses of the poor Scheduled Caste and displaced people who have already purchased the land and who have already constructed their houses? In spite of all that, the houses and the land would be acquired. People purchase the land at the rate of Rs. 7 or Rs. 8 per square yard. The Government is acquiring this land at the rate of Rs. 1.50 rwr square yard. After doing some development they are going to sell it at the rate of something like Rs. 80 per square yard. Is it a *bania* shop to exploit the poor and benefit the rich? What is it they are doing? I fail to understand why they do these things. I just want to draw the attention of the Government to the griev-

ance of the poor people over such business of the Government, and would request them to see that those who have already purchased sites may be allowed to stay there. Madam, have I taken more time?

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is already 1.30. You have taken nearly 17 or 18 minutes.

SHRI B. K. GAIKWAD: Then I resume my seat.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at thirty minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at half past two of the clock, the VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RAMCHANDRA SATHE) in the Chair.

श्री राम सहाय (मध्य प्रदेश) : उपासभाध्यक्ष महोदया, यह बजट जिस पर हम बहस कर रहे हैं, मेरा ऐसा विचार है कि पिछले वर्षों में जिस तरह के बजट आये हैं, उनसे यह बहुत ही अच्छा है । टी० टी० कृष्णमाचारी जी से जैसी अपेक्षा की गई थी, उसी प्रकार का बजट उन्होंने हाउस के सामने रखा है और निस्सन्देह उसमें बहुत सी सहूलियतें दी गई हैं ।

अभी हमारे देश के सामने कुछ खास खास समस्याएं हैं । कुछ तो हमारे घर से, हमारे देश से सम्बन्ध रखने वाली हैं और कुछ विदेशों से सम्बन्ध रखने वाली हैं । हमारी जो भी इंटरनल दशा है, उसके बारे में दो प्रश्न हमारे सामने बहुत जबर्दस्त हैं । पहला प्रश्न जो अभी हाल में उत्पन्न हुआ है, वह भाषा का है । जहां तक भाषा का प्रश्न है, सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि मैं सदैव से हिन्दी में ही बोलता रहा हूं । हिन्दी में बोलते रहने के साथ ही मैंने कभी किसी के अंग्रेजी में बोलने पर आपत्ति नहीं की और न मैंने कभी ऐसा ही रुख लिया जिससे हमारे साथियों को, दक्षिण के रहने वालों को, यह प्रतीत हो कि मैं हिन्दी उनपर लादना चाहता हूं । लेकिन कुछ हालात देश में ऐसे पैदा हुये और कुछ हमारे मुखालिफ लोगों ने ऐसा वातावरण पैदा किया जिससे हमारे देश की ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि हमारे दक्षिण वाले भाई यह समझने लगे कि हिन्दी के प्रचार से कुछ उनको हानि पहुंचेगी और जितनी उनको उन्नति करनी चाहिये, उतनी उन्नति वे नहीं कर सकेंगे । हमारे उत्तर के लोग इससे कुछ विशेष चिंतित हैं । लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि यह स्थिति जो उत्पन्न की, वह उत्तर के रहने वाले हिन्दी स्पीकिंग लोगों ने ही उत्पन्न की । कारण उसका यह है कि इन 15 वर्षों के अन्दर, अगर वे हिन्दी से प्रेम रखते थे और वे हिन्दी बोलना चाहते थे और अगर वे स्वयं हिन्दी में बोलते रहते, तो हमारे दक्षिण के भाइयों को यह जरूर अहसास हो जाता कि हम को किसी न किसी दिन हिन्दी पर निश्चय ही आना पड़ेगा । लेकिन वे स्वयं अपनी शान इसमें समझने लगे कि वे अंग्रेजी में ही बात करें। हिन्दी में बात करने में उनको बहुत बुरा मालूम होने लगा और उसमें उन्हें कुछ इनफीरियरिटी काम्पलेक्स सताने लगा । मैंने देखा है कि जो अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल भी नहीं सकते, वे अंग्रेजी में बोलने का प्रयत्न करते हैं । हिन्दी में बोलने में एक डिसऐडवांटेज यह जरूर है कि हमारे प्रेस गैलरी वाले, चाहे वे हिन्दी समाचार पत्रों के हों, चाहे किसी और समाचार पत्रों के हों, वे हिन्दी में बोलने वालों की रिपोर्ट ठीक तरीके से नहीं देते । या तो वे अच्छी तरह से हिन्दी को समझ नहीं पाते हों, इस वजह से ऐसा करते हों, या जो भी कारण हों, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन इस वजह से भी कुछ लोगों को अंग्रेजी में बोलने का प्रोत्साहन मिला है । उनका प्रचार इस तरह से हो या न हो,

[श्री राम सहाय]

यह तो एक इम्मैटीरियल सी चीज है, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि हमारे हिन्दी भाषा भाषी जो लोग हैं, वे अगर यह चाहते थे कि हिन्दी को अपना स्थान प्राप्त हो, तो निश्चय ही चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो हिन्दी में बोल सकता था, उसे हिन्दी में बोलना चाहिये था। यह मैं मानता हूं कि जो हिन्दी में हमारे भाई नहीं बोल सकते थे, उनको निश्चय ही इतना मौका देना चाहिये था कि जिस भाषा में वे बोलना चाहें, जिस भाषा में व उत्तर देना चाहें, जिस भाषा में वे अपनी बात करना चाहें, उनको उसकी पूर्ण स्वतंत्रता रहती। यदि ऐसा हुआ होता, तो निश्चय ही आज यह वादविवाद न खड़ा होता। मेरा अब भी यह खयाल है कि अगर हम हिन्दी भाषा भाषी लोग इस प्रकार का रवैया अख्तियार कर लें, और हमारे जो दक्षिण के भाई हैं, उनको यह निश्चय हो जाय कि दरअसल ऐसी स्थिति है, तो निश्चय ही न हमको अपने कांस्टिट्यूशन में, अपने संविधान में, तब्दीली करने की जरूरत है और न हमको जो भाषा का ऐक्ट है उसमें ही किसी तब्दीली की आवश्यकता है। मैं तो समझता हूं कि हम को निश्चय ही इसी प्रकार का रवैया रखना होगा और रखना चाहिये। जब तक हम अपने इतने बड़े देश में सब जगह के लोगों की जो उनकी इच्छाएं हैं और जो उनकी समाज सम्बन्धी बातें हैं, उन सबका पूरा पूरा ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक हम निश्चय ही इतने बड़े देश को अपने साथ ले कर के कदापि नहीं चल सकेंगे। तो मेरा इस भाषा के सम्बन्ध में यही नम्र निवेदन है हिन्दी भाषी लोगों से कि अब भी समय है और वे इस प्रकार का रवैया रखें और इस प्रकार का अपना व्यवहार रखें कि जिससे किसी प्रकार की गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे दक्षिण के भाइयों में तनिक भी उत्पन्न न होने पाये। अगर हमने यह रवैया रखा, तो निश्चय ही दो चार साल के अन्दर हम उन्हें इत्मीनान करा सकेंगे। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे सत्य-नारायण जी जो हैं, वे बेचारे वहां वर्षों से हिन्दी प्रचार का काम कर रहे हैं, उनके द्वारा भी मालूम हुआ और मुझे स्वयं भी वहां दक्षिण के बारे में मालूम है कि वहां निश्चय ही हिन्दी का प्रचार हो रहा है। हमारे दक्षिण के भाई इतने इंटेलिजेंट हैं कि मैं समझता हूं कि जो आज उनको यूनियन सेक्रेटेरियट में प्रमुखता मिली हुई है, वह निश्चय ही आगे भी कायम रहने वाली है और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हिन्दी अगर होगी तो जिस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजी में, जो एक बिलकुल विदेशी भाषा है, उसमें इतना अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया है, उसी प्रकार से हिन्दी में उन्हें वही स्थान प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके लिये जो समय का सवाल है, वह समय मेरे खयाल से हम लोगों को देना चाहिये और जब तक हम उतना समय उनको दें, उस वक्त तक शासन का यह कर्तव्य है कि वह इस प्रकार की सहूलियतें उन्हें अवश्य दे, जिससे इस भाषा के प्रश्न पर उनको सर्विसेज इत्यादि में किसी प्रकार की हानि न पहुंचने पाये। जब तक हम इस प्रकार का रवैया नहीं रखेंगे, तब तक निश्चय ही कोई अच्छा नतीजा नहीं निकाल सकते। एक तो यह प्रश्न आज हमारे सामने है।

हिन्दी के अलावा जो दूसरा घरेलू प्रश्न हमारे सामने है, वह भावों के सम्बन्ध में है और यहां खाद्यान्न उत्पन्न करने के सम्बन्ध में है। निश्चय ही हमने इंडस्ट्रीज और कुछ चीजों में बहुत काफी उन्नति की है। इसमें कोई शक नहीं है कि बिजली तथा इरिगेशन के जितने साधन हम मुहैया कर सके हैं, वे निश्चय ही बहुत अधिक हैं और उनका पूरा पूरा उपयोग भी हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी अपने देश में अनाज उत्पन्न करने के लिये जो पर्याप्त साधन हमें पहुंचाने की आवश्यकता है, वह हम अभी तक नहीं कर पाये हैं। हम बाहर से जितना अनाज मंगाते हैं, उसका थोड़ा प्रोपोरशन अगर हम इसमें खर्च करें, और अनुभवी लोगों की इसमें सहायता लें, तो हमें

बहुत सफलता मिल सकती है। अनुभवी लोगों से महज मेरा मतलब उनसे नहीं है, जो कोई डिग्री प्राप्त करके यह काम करते हैं और जिन को फील्ड वर्क का कोई ज्ञान नहीं होता है। असल में जो फील्ड वर्क करने वाले हैं, उनकी सहायता से यह काम होना चाहिये। और हमारे देश में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां हम अपना रकबा गेहूं इत्यादि को उत्पन्न करने का क्षेत्र, बढ़ा सकते हैं। मैं निवेदन करूं कि हमारे मध्य प्रदेश में जहां डकैती की समस्या है, भिंड और मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, उनमें मेरा विश्वास है और गवर्नमेंट ने भी एक्सपेरिमेंट किया है कि जो बीहड़ हैं उनको अगर आबाद किया जाय तो एक चौथाई खर्चा उसके आबाद होने से ही मिल जाता है और तीन चौथाई कीमत ही सरकार को खर्च करनी पड़ती है—तो अगर वहां यह किया जाय तो उससे दो समस्यायें हल हो जाती हैं, एक तो डाकू समस्या हल हो जाती है और दूसरे लोगों को रोजगार मिल जाता है और फिर हम अनाज का भी अच्छी तरह से उत्पादन कर सकते हैं। तो मेरा विचार है कि विदेशों में रुपया खर्च करने के बजाय, उन पर निर्भर रहने के बजाय हमारे देश में जो साधन हैं उनको ही जुटाएं तो निश्चिय ही हमारी कठिनाई दूर हो सकती है।

अब जो दूसरी समस्या हमारे सामने है वह चीन और पाकिस्तान की है। वह बाहर के देशों से सम्बन्ध रखने वाली समस्या है और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हमारी गवर्नमेंट कार्य कर रही है उससे ज्यादा अच्छा काम हो नहीं सकता, उसमें मुझे कोई त्रुटि मालूम नहीं पड़ती है, सिर्फ यही खयाल है कि बहुत सतर्कता से काम करें और कच्छ खाड़ी आदि की जो दिक्कतें हमारे सामने आई हैं उस प्रकार की दिक्कतें हमारे सामने नहीं आनी चाहिए।

बजट के सम्बन्ध में जो विशेष रूप से सम्बन्धित बात है वह यह है कि हमारे जितने मिनिस्टर महोदय हैं उन सब से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आती है, पबलिक एकाउंट्स कमेटी की जो रिपोर्टस आती हैं उन सब पर वे स्वयं तवज्जह करें और वे स्वयं देखें कि दरअसल में जो त्रुटि है वह दूर होती है या नहीं। मैं आपसे अर्ज करूं कि मेरा यह खयाल था कि हमारे सेक्रेटेरियट के सभी लोग बहुत अच्छी तरह काम करते हैं लेकिन मेरा वह खयाल, मेरा वह विश्वास, इन दिनों कुछ हट सा गया है, कारण यह है कि मैंने सन् 20 से लेकर उसके बाद सन् 1947, 1948 तक की रिपोर्टें देखीं तो 47-48 की पबलिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट की और आडिटर जनरल की रिपोर्ट की जो हालत थी उससे बेहतर तो क्या, मैं कहता हूं कि उससे भी गई गुजरी आज हालत है। कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने को समर्थ नहीं पाता। मैंने देखा है कि हमारे जो सेक्रेटरीज और जो आफिसर्स आते हैं वे अधिकतर किसी नकिसी प्रकार से जवाबों की पूर्ति करते हैं, जो त्रुटि है उसको शील्ड करने की, छिपाने की कोशिश करते हैं। तो जब इस प्रकार की हमारे देश की हालत है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसी प्रकार से कार्य सुचारु रूप से टले। मेरा तो विश्वास है है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय अगर इस चीज को देखेंगे तो निश्चय ही हम और भी कमी करों में कर सकते हैं बशर्ते कि यह जो वेस्टेज है, खराबी है, चोरी और खयानत है, इस प्रकार के जो कार्य हैं उनको हम रोक कर सकें। आप गौर करिए कि हमने देखा कि तीन लाख रुपये की सीमेंट एक डिपार्टमेंट से चोरी जाती है—समझ में नहीं आता है कि तीन लाख रुपये की सीमेंट कैसे चोरी हो जाती है—वह दरअसल में चोरी नहीं है, हमारे खयाल से उसमें फर्जी जमाखर्च हुआ क्योंकि जब गेट कीपर मौजूद है और सारी बातें मौजूद हैं तो तीन लाख की सीमेंट की चोरी निश्चय ही नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार से कई त्रुटियां हैं। हवाई जहाज की इस कदर हमें तकलीफ है लेकिन सैकड़ों हवाई जहाज पड़े हुए हैं और वे बेकार हो गए हैं और इसलिए बेकार हो गए हैं कि उनका

[श्री राम सहाय]

कोई सामान ही नहीं मिलता। तो जिस सीमेंट के बारे में मैंने जिक्र किया उसमें एक स्टोर कीपर, एक बेचारा गरीब छोटा सा नौकर, ससपेंड कर दिया गया, अलग कर दिया गया लेकिन क्या कुछ खामियां पूरी होती हैं? कौन अफसर जिम्मेदार है इसका कोई लेखा जोखा नहीं। अगर एक सेक्रेटरी, एक हेड आफ दि डिपार्टमेंट चला जाता है, चाहे वह पेंशन पर यहीं मौजूद हों और उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता हो लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाती . . . .

श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय : : कौन सा प्राजेक्ट है ?

श्री राम सहाय : यह मैं मुनासिब नहीं समझता कि उन चीजों को ज्यादा विस्तार से कहूं। मेरा यही निवेदन है कि जितने मिनिस्टर महोदय हैं वे कृपा कर के खुद इस चीज को देखें कि लाखों रुपयों की, करोड़ों रुपयों की मशीनरी बेकार पड़ी हुई है और उसका कोई उपयोग नहीं होता और दूसरी दूसरी मशीनरीज आ रही हैं। तो इसी प्रकार रोड रोलर की जरूरत है, आयल की जरूरत है लेकिन करोड़ों रुपयों का कोयला खरीदा गया। तो इस प्रकार की बहुत सी त्रुटियां हैं। मैं समझता हूं कि इन बातों पर हमारे मंत्री महोदय विचार करेंगे और देखेंगे और इसको अपनी प्राइमरी ड्यूटी समझेंगे कि इस प्रकार जो त्रुटियां वर्षों से होती चली आ रही हैं उनको दूर करने का प्रयत्न करें।

श्री गंगाशरण सिंह (बिहार) : जनाब वाइसचेयरमैन साहिबा, बजट पर कुछ बोलते समय सबसे पहले और इसकी तफसील में जाने से पहले इस बजट का जो साधारण बाह्य रूप है और जो इसका असर देश के भिन्न भिन्न क्षेत्र के के लोगों पर पड़ा है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि यह बजट पुरानी पद्धति से थोड़े दूसरे रास्ते पर कुछ हट कर एक अपना रास्ता बनाने की चेष्टा का प्रमाण है। इसमें हमारे वित्त मंत्री ने अपने ज्ञान और बुद्धि की दक्षता से जैसा उपयोग हो सकता था वैसा किया है और यही कारण है कि आज दो सप्ताह से अधिक इस बजट को पेश हुए हो गए फिर भी भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग आज तक इस बजट का देश के भावी आर्थिक कार्यक्रम पर आर्थिक अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में भिन्न भिन्न मत रखते हैं और इसे तफसील के साथ शायद बतला नहीं सकते। उन्होंने इस खयाल से कि अगला जो चौथा प्लान आने वाला है उसके चलते जो लोगों की आशंका है—जैसा कि बिजली की कड़क का और बिजली के गिरने का सम्बन्ध है उसी तरह से हर प्लान के पहले लोगों को यह आशंका होती है कि आगे से टैक्स बढ़ने वाला है—हमको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा हम पर ज्यादा बोझा पड़ेगा उस आशंका को दूर करने के लिए उन्होंने इसमें प्रयत्न किया है कि लोग यह समझें कि आगे जो चौथे प्लान का बोझ आने वाला है उसके लिए कोई नया टैक्स शायद उन्हें नहीं देना पड़ेगा। मैं नहीं जानता हूं कि वह कहां तक इस प्रयत्न में सफल होंगे मगर जो बजट अभी उन्होंने रखा है उसमें उनका यही प्रयत्न मालूम होता है—इसे वह स्पष्ट शब्दों में कहें या न कहें।

बजट पर चर्चा करते समय एक बात का बार बार जिक्र किया गया, कल हमारे मित्र श्री बलिराम भगत ने भी किया और दूसरे लोगों ने भी चर्चा की —एकानामिक ग्रोथ की—आर्थिक उन्नति की और जब कभी सोशलिज्म की चर्चा हुई,—यह कहा गया कि यह बजट समाजवाद की तरफ नहीं ले जाता है तो बार बार हवाला दिया गया आर्थिक उन्नति का एकानामिक ग्रोथ का—लेकिन बहुत अदब से मैं कहना चाहता हूं कि आर्थिक उन्नति या एकानामिक ग्रोथ

कोई समाजवाद की मोनोपली नहीं है एक पूंजीवादी समाज में अधिनायकतंत्र में भी आर्थिक उन्नति हो सकती है उसमें भी एकानामिक ग्रोथ हो सकती है । असल अन्तर होता है पूंजीवादी समाज में अधिनायकतंत्र में और समाजवादी समाज में, जनतंत्र में कि जो आर्थिक उन्नति होती है उस आर्थिक उन्नति से जो लाभ होता है वह समाज के किस अंश को किस अंग को मिलता है उसका एक समुचित बटवारा होता है या नहीं होता है । यह प्रश्न उसकी जड़ में उस उन्नति की जड़ में होता है नहीं तो देश में कुछ मुट्ठी भर लोग ज्यादा पैसा कमाते रहें, कुछ के हाथों में आर्थिक और राजनैतिक दोनों सत्ता केन्द्रित होती रहे और बाकी लोग गरीब बने रहें बाकी लोग परेशान बने रहें तो उसे न समाजवाद कहेंगे और न सही अर्थ में उन्नति कहेंगे । दूसरी बात यह भी है कि जब हम आर्थिक उन्नति की बात करते हैं तो हमें उन्नति के साथ साथ यह भी देखना चाहिए कि उत्पादन के जो साधन हैं उन साधनों पर किन का अधिकार और प्रभाव है ? उत्पादन के मूल में जो चीजें हैं उन पर समाज का अधिकार है या किन्हीं व्यक्तियों का अधिकार बना हुआ है । साथ ही साथ यहभी देखना होगा कि उपभोग्य वस्तुओं के वितरण का और जो आमदनी है उस के विभाजन का तरीका कैसा है ? वह समुचित रूप से वितरित और विभाजित होता है या नहीं होता है । उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमें लगता है जो कुछ भी आमदनी हमारी होती है जो कुछ भी आर्थिक उन्नति होती है उसका बंटवारा किस प्रकार होता है यह पता लगाने के लिये कई वर्षों से चेष्टा हो रही है ताकि उसके सम्बन्ध में कुछ किया जाय लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि उसके सम्बन्ध में कुछ विशेष किया जा सका है । जो कुछ आर्थिक उन्नति होती है उसका अधिकांश हिस्सा नीचे के तबके को मिलने की बजाय ऊपर के तबके को मिलता है और नीचे के तबके के लोगों की अवस्था ज्यों की त्यों बनी रहती है । मैं कहना चाहता हूं अपने चतुर और बुद्धिमान वित्त मंत्री से, कि इस सम्बन्ध में उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिये, चूंकि जब कभी मैं देखता हूं कोई ऐसी शिकायत की जाती है तो कहा जाता है कि ऐसी कार्यवाहियां हम कर रहे हैं जिससे नीचे तबके के लोगों को फायदा होने वाला है, और उससे उल्टा ही काम होता है, उसका परिणाम उल्टा ही पड़ता है । अभी मैं एक तत्काल उदाहरण आपको बतलाऊं । टेक्सटाइल की एक्साइज ड्यूटी में पचास प्रतिशत कमी हुई है और हर आदमी के दिल में यह आशा बंधी कि इससे जो सूती कपड़े होंगे, सूती चीजें होंगी उनके दाम में कमी होगी । मेरा थोड़ा सम्बन्ध जो कमेटी बनी है टैक्सटाइल की उससे है । मैंने इसके बारे में थोड़ा पता लगाने की चेष्टा की तो मालूम यह हुआ कि जो कुछ अभी सरकार ने कहा है जो कुछ सरकार ने निर्णय किया है उसका परिणाम यह होगा कि कपड़े की कीमत घटने के बजाय बढ़ेगी ही । इसको मैंने एक से नहीं कई दूकानदारों से दूसरे लोगों से पूछा और पता लगाया और उन्होंने बतलाया कि यह ठीक है कि टैक्सटाइल की एक्साइज ड्यूटी पचास प्रतिशत कम हो गई है । मैंने धोती और साड़ी के बारे में पता लगाया जिसकी सब से ज्यादा आम तौर पर खपत होती है । उन्होंने बताया एक्साइज ड्यूटी कम होने से पन्द्रह पैसे सोलह पैसे तक की कमी होगी दामों में लेकिन कपड़े की कीमत तय करने के लिये जो मल्टीप्लायर सिस्टम है उसके चलते और टैक्स के कारण रुई की कीमत जो बढ़ी है उसके चलते उन्हीं धोतियों और साड़ियों की कीमत 26 पैसे से 30 पैसे तक बढ़ जायेगी । इसका परिणाम यह होगा कि कुल मिला कर जो उपभोक्ता है जो धोती और साड़ी खरीदने वाला है एक्साइज ड्यूटी कम होने के बावजूद उसे प्रत्येक साड़ी और धोती पर 10 से 15 पैसे तक बेशी देने पड़ेंगे । अखबारों में जब खबर छपी तो जनता ने समझा कि टैक्सटाइल

[श्री गंगाशरण सिंह]

की एक्साइज ड्यूटी कम हो गई तो चीजें हमें सस्ती मिलेंगी और दूकान में आयेंगे तो बजाय सस्ती के 10 पैसा बेशी उनको देना पड़ेगा। यह पता नहीं जान बूझ कर किया गया है या जो हमारी प्रथा चली आ रही है उसका परिणाम है क्योंकि बाहर से कहा जाता है कि दाम कम हुआ लेकिन असल में वह बढ़ जाता है। आखिर जो ये बातें होती हैं उनके मूल तथ्यों के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई टैक्सेशन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। यह ठीक है कि देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये देश के कामों को चालू रखने और उनमें प्रगति लाने के लिये टैक्सेशन होता है लेकिन टैक्सेशन में एक दृष्टिकोण यह भी रहता है—जैसा स्वयं हमारे वित्त मंत्री ने कहा था—कि जिन लोगों को मुनाफा बहुत अधिक होता है उस मुनाफे का थोड़ा हिस्सा सरकार के, जनता के और जन कार्य में लग सके और सरकार के खजाने में आ सके—यह भी टैक्सेशन का दृष्टिकोण रहता है। हमारे वित्त मंत्री ने भी ऐसा कहा था, लेकिन हमारा तजुर्बा है कि जब कोई टैक्स लगता है तो मुनाफे में कमी नहीं होती है, मुनाफे के हिस्से में से सरकार के पास नहीं जाता है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, जो कन्ज्यूमर है, उपभोक्ता है, उन पर वह बोझ पड़ता है। कभी यह कहा जाता है कि हम किसी चीज में छूट इसलिये दे रहे हैं कि उससे उपभोक्ता को थोड़ी बहुत राहत मिले लेकिन वह राहत उपभोक्ताओं को मिल नहीं पाती। बाहर की चीनी पर लगाया गया टैक्स मुझे बार बार इस सम्बन्ध में याद आता है। जहां तक चीनी के कारखानों का सवाल है मुझे स्मरण है श्री जान मथाई की अध्यक्षता में जो टैरिफ कमीशन बना था और जिस टैरिफ कमीशन की सिफारिश पर बाहर की चीनी पर टैक्स लगाया गया था, उस टैरिफ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में निश्चित रूप से कहा था कि हिन्दुस्तान में बाहर से आने वाली चीनी पर टैक्स लगाने का जो सुझाव हम दे रहे हैं उसके पीछे हमारी यह धारणा है कि जो गन्ना उपजाने वाले हैं उनको राहत मिले, जो कन्ज्यूमर हैं उनको राहत मिले, जो उपभोक्ता हैं उनको राहत मिले। स्पष्ट रूप से रिपोर्ट में यह लिखा था कि जो टैक्स हम लगाने को कह रहे हैं उसके पीछे हमारी यही धारणा है, यही भावना है। लेकिन हुआ क्या? जो बात हुई, जो टैक्स लगाया गया, जिसके चलते अभी तक उपभोक्ता को चीनी की अधिक कीमत देनी पड़ती है, उसका पैसा गन्ना पैदा करने वाले के पास जितना जाना चाहिये था वह नहीं गया और कभी उपभोक्ता को राहत नहीं मिली और बीच में जो मिल मालिक था उसको ज्यादा राहत मिली। वही परम्परा जो 1929 में और उसके बाद 1932–33 में कायम हुई थी वही आज तक चली आ रही है, आज भी वही व्यवस्था कायम है। मैं बड़े अदब से वित्त मंत्री से कहना चाहूंगा कि वे जरा इस बात को भी सोचने की कोशिश करें कि जब कभी वे कोई छूट देते हैं तो वह छूट नीचे के तबके तक कैसे नहीं पहुंच पाती है, वह कौनसा छाता लगा हुआ है जो बारिश को रोक लेता है और नीचे जमीन सूखी रह जाती है। इस पर सबसे पहले हम सबको ध्यान देना चाहिये।

आज हमारे देश में एक तरह की प्रतिद्वंदिता चल रही है। आमतौर से देश के लोग—गरीब लोग, मध्य वर्ग के लोग, कमाने वाले लोग—आज समाजवाद के पक्ष में हैं। लेकिन एक ऐसा तबका भी है जो हमारे देश में है जो अभी तक समाजवाद को स्वीकार नहीं कर सका है, समाजवाद के प्रति जिसकी धारणा आज भी अच्छी नहीं है और जो समाजवाद को अच्छी निगाहों से नहीं देखता है। आज भी वे चाहते हैं कि समाजवाद की चर्चा बन्द होनी चाहिये। अगर हम सचमुच समाजवादी हैं, हमारी सरकार समाजवादी है, तो हमें कोई एसा

हथियार उनके हाथ में नहीं देना चाहिये जो आज समाजवाद की मुखालिफत करना चाहते हैं। और सब से बड़ा हथियार आप तब उनको देते हैं जब आपकी पबलिक अंडरटेकिंग्स मुस्तेदी के साथ, चुस्ती के साथ, नहीं चलती हैं, उनमें घाटा होता है, उनका उत्पादन जब कम होता है और वह मजाक की चीज बन जाती है तो जो समाजवाद के विरुद्ध हैं उनको ऐसा हथियार देते हैं यह कहने के लिये कि यह समाजवाद कभी चलने वाला नहीं है, बिना व्यक्तिगत प्रेरणा के, बिना व्यक्तिगत लाभ के, मुनाफे के, समाज का कोई काम चल नहीं सकता है। हम देखते हैं हमारी पबलिक अंडरटेकिंग्स में जो घाटा होता है, उस घाटे से सिर्फ हमारी आर्थिक क्षति ही नहीं होती है बल्कि हम समाजवाद को बहुत बड़ा धक्का देते हैं और समाजवाद के लिये जो वातावरण तैयार होना चाहिये उस वातावरण को तैयार करने में बाधक होते हैं। हमारी पबलिक अंडरटेकिंग्स में जो घाटा होता है, उनमें जो चुस्ती की कमी है, और उनमें तरह तरह की जो खराबियां हैं उनके चलते जो आमतौर से लोग तुलना करते हैं कि यही काम एक कैपिटलिस्ट कर रहा है, पूंजीपति कर रहा है और यही काम सरकार कर रही है। और जब सरकार का काम उस मुस्तैदी से नहीं होता है, सरकार के काम में वह मुनाफा नहीं होता है और चुस्ती नहीं होती है जो व्यक्तिगत रूप से काम करने वाले और पूंजीपति के काम में होती है—तो वह वातावरण समाजवाद के लिये अच्छा नहीं होता, इसके चलते समाजवाद आज मजाक की चीज हो गया है। आज आप रेल का सफर कीजिए, रेल में खाना खराब मिलेगा तो आमतौर से लोग कहेंगे कि अरे भाई, अब वह नेशनलाइज हो गया है, अब इसका राष्ट्रीयकरण हो गया है—यह एक मुहावरे की तरह, मजाक की चीज, बाजार में, स्टेशन में, हर जगह, हो गई है। अगर आप समाजवाद लाना चाहते हैं तो लाइये, नहीं लाना चाहते हैं तो नहीं लाइये, लेकिन समाजवाद को मजाक की चीज बना कर भविष्य के लिये समाजवाद का दरवाजा मत बन्द कीजिए। आज पबलिक अंडरटेकिंग्स के जरिए से हम समाजवाद के लिये वातावरण नहीं तैयार कर रहे हैं बल्कि उसे मजाक की चीज बना रहे हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इन पबलिक अंडरटेकिंग्स के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिये और उनको ज्यादा एफिशियेन्सी के साथ, ज्यादा मुस्तैदी के साथ, चुस्ती के साथ चलाना चाहिये जिससे यह आदर्श उपस्थित हो सके कि समाजवादी प्रबन्ध पूंजीवादी प्रबन्ध से ज्यादा अच्छा, ज्यादा एफिशियेन्ट, ज्यादा मुनाफा देने वाला और ज्यादा लाभकारी होता है।

शुरू से ही, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से बेकारी के संबंध में तरह तरह के आश्वासन दिये गये। कभी कहा गया बेकारी दूर हो जायगी, कभी कहा गया जो बेकारी है उससे आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन हम क्या पाते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्ति पर है लेकिन बेकारी पहले से बढ़ी ही है। मुझे तो रामायण की वह चौपाई याद आती है जब लंका में हनुमान जा रहे थे और सुरसा ने उनको रास्ते में रोका। सुरसा ने ज्योंही अपना मुंह उनको निगलने के लिए बढ़ाया तो हनुमान ने अपने शरीर को उससे बड़ा बना लिया। तुलसीदास ने लिखा है:

"जस जस सुरसा बदन बढ़ावा,
तासु दुगुन कपि रूप दिखावा"

तो सुरक्षा ने जैसे ही मुंह बढ़ाया, वैसे ही हनुमान जी ने दुगुना स्वरूप बढ़ाया। तो हमारी दशा भी वैसी ही है। जैसे जैसे हमारी सरकार कोशिश करती है वैसे ही बेकारी बढ़ती ही जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षितों की बेकारी काफी बढ़ रही है। एक तरफ तो हमारे यहां अशिक्षित लोग हैं, लोगों में शिक्षा का अभाव है, ऐसे लोग हैं जो शिक्षित नहीं हैं, और दूसरी तरफ शिक्षित लोग हैं जो बेकार हैं। एक ओर शिक्षितों को काम नहीं मिलता दूसरी ओर हमारे यहां जहां किसी काम में विशेषज्ञों की जरूरत होती है तो उसकी कमी पड़ती है।

[श्री गंगाशरण सिंह]

मैं यह तो नहीं कह सकता कि कभी आर्डिनेन्स या आर्डर के जरिये से टैक्सेशन का काम होने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है लेकिन इतना मैं जरूर सरकार से कहना चाहूंगा कि आर्डिनेन्स के जरिये या आर्डर के जरिये टैक्सेशन का काम जितना कम किया जाय उतना ही अच्छा होगा, इसलिये नहीं कि इस सरकार की नीयत पर मुझे कोई शक है, बल्कि एक ऐसी परम्परा हो गई है कि जो काम हम करते हैं इस जनतांत्रिक युग में, हम इस बात का ख़याल नहीं करते कि हम ऐसी परम्परा को जन्म दे रहे हैं जो जनतंत्र के लिये घातक है या जो जनतंत्र में अविश्वास पैदा करने वाला है। मैं बिलकुल इसको "रूल आउट" तो नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कहता कि इसको कभी नहीं करना चाहिये लेकिन जहां तक हो सके, आर्डर और आर्डिनेन्स के जरिये टैक्सेशन का काम नहीं करना चाहिये। यही जनतंत्र के लिये और हमारे देश के लिये अच्छी बात होगी। जो टैक्सेशन हुआ उसके खिलाफ मैं नहीं हूं लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि ठीक जब पार्लियामेन्ट का सेशन होने वाला है, उसके ठीक पहले, आर्डिनेन्स लाने की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसी अत्यावश्यकता क्या थी? इस बात का मैं आज तक जवाब नहीं पा सका हूं, इसका कारण नहीं मालूम कर सका हूं। सिर्फ टैक्सेशन का मामला नहीं है। 24 दिसम्बर को पार्लियामेन्ट का अधिवेशन समाप्त हुआ था और 29, 30 दिसम्बर को कम्यूनिस्टों के खिलाफ कार्यवाही की गई। एक सप्ताह के भीतर क्या ऐसी बात हो गई थी? पार्लियामेन्ट को सरकार ने खबर क्यों नहीं दी। तो सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं है, सरकार की एक परम्परा हो गई है कि आर्डिनेन्स के जरिये, आर्डर के जरिये, वह काम करती है जो सचमुच में पार्लियामेन्ट को करना चाहिये और पार्लियामेन्ट की कमेटी को करना चाहिये। इस ओर मैं विशेष रूप से वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

3 P.M.

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हमें देश के आर्थिक और औद्योगिक तंत्र को अच्छी तरह से चलाना है, सही रूप में चलाना है, तो जिस तरह हमने दूसरी सर्विसेज कायम की हैं, उसी तरह मेरा यह भी सुझाव है कि हमें आर्थिक और औद्योगिक सर्विस कायम करनी चाहिये और इन्डस्ट्रियल इकानोमिक सर्विस की बुनियाद डालनी चाहिये तथा उसका कैडर तैयार करना चाहिये। जब हम इस तरह की बात करेंगे तब ही आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक हमारे सिविलियन और पोलिटिशियन्स दो तरह के लोग ही इन क्षेत्रों में काम करते आ रहे हैं। जिस तरह से 'अमृतधारा' किसी भी बीमारी के लिए दे दी जाती है, पैर से लेकर सिर की कोई भी बीमारी हो उसके लिए 'अमृतधारा' दे दी जाती है और कहा जाता है कि इसके देने से फायदा होगा, उसी तरह से ये दो वर्ग के लोग हमारे राजनीतिज्ञ और सरकारी अधिकारी, चाहे किसी तरह का काम हो, फैक्टरी चलानी हो, गवर्नमेंट चलाना हो, किसी संस्था को चलाना हो, कोई भी काम हो, वहां या तो कोई राजनीतिज्ञ भेज दिया जायेगा या कोई सरकारी अधिकारी भेज दिया जायेगा। ऐसा मालूम देता है कि आज के जमाने में किसी चीज को चलाने के लिए किसी खास जानकारी की जरूरत नहीं रह गई है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस तरह की सर्विस बनाने के लिए खास ध्यान दिया जाना चाहिये और सारे देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए इस तरह की सर्विस बनाने की बुनियाद आज ही डाल देनी चाहिये।

एक सबसे बड़ी बात आज यह हो रही है, आज बहुत सी कार्यवाहियां ऐसी हो रही हैं जिनके चलते सरकार में लोगों का अविश्वास पैदा होता और बढ़ता है। मैं सिर्फ सरकार की आलोचना की दृष्टि से यह बात नहीं रख रहा हूं, सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना में मेरी रुचि नहीं है। लेकिन मैं पूरी

जिम्मेदारी के साथ यह बात कहना चाहता हू और जो मैंने खुद अनुभव किया है कि वह अपने कार्रवाइयों की वजह से देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अविश्वास पैदा कर रही है। उनमें से यह एक भी है कि सरकार की ओर से भिन्न भिन्न आंकड़े प्रकाशित किये जाते हैं जो एक दूसरे के प्रतिकूल होते हैं। एक ही सरकार की भिन्न भिन्न संस्थाएं एक ही विषय में भिन्न भिन्न परस्पर विरोधी आंकड़े प्रकाशित करती है। जो आदमी विशेषज्ञ नहीं हैं या दूसरा कोई भी आदमी इस तरह की चीज पर किस तरह विश्वास करे। वह सरकार की एक संस्था द्वारा दिये गये आंकड़ों पर विश्वास करे या दूसरी संस्था द्वारा दिये गये आंकड़ों पर विश्वास करे? यह जो परम्परा है आज ही नहीं चली है बल्कि मुझे स्मरण है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में योजना आयोग की तरफ से कहा गया था कि हमारे यहां उस अवधि में खाद्यान्न का उत्पादन 750 लाख टन हुआ। नेशनल सैम्पुल सर्वे जो काम करता है वह भी सरकार के पैसे से ही काम करता है और उसने कहा कि उसी अवधि में 960 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। अब दोनों में से किस की बात को सही समझा जाय, यह कहना मुश्किल है। इस तरह के दर्जनों उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं । मैं सदन का ज्यादा समय इस संबंध में नहीं लेना चाहता हूं कि एक ही विषय में सरकार के भिन्न भिन्न संस्था द्वारा भिन्न भिन्न तरह के कितने आंकड़े दिये गये हैं । हम इस तरह के आंकड़ों के आधार पर आगे की कार्यवाई किस प्रकार कर सकते हैं ?

यह बात ठीक है कि आज हमारे सामने जितनी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं का समाधान हम एक साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें समस्याओं को प्राथमिकता देनी चाहिये, प्रायरिटी देनी चाहिये और प्रायरटी देने में हमको यह खयाल रखना होगा कि जिस जिस चीज का हमारे जीवन से, हमारे देश से, हमारी स्वतंत्रता से, हमारे अस्तित्व से विशेष संबंध है उसी को हमें पहले करना चाहिये । आज हमारे सामने देश की सुरक्षा का प्रश्न है, खाद्यान्न का प्रश्न है, आज हमारे सामने देश के स्वास्थ्य का प्रश्न है आज हमारे सामने शिक्षा का प्रश्न है और ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे मुख्य प्रश्न हैं और जिन्हें हमें और चीजों के मुकाबले में प्राथमिकता देनी चाहिये । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने जो प्राथमिकता का क्रम रखा है वह देश के लिए अब तक घातक सिद्ध हुआ है । कृषि पर जोर दिया जाना चाहिये था, कृषि के संबंध में जो प्राथमिकता दी जानी चाहिये थी वह आज तक नहीं दी गई है। शिक्षा के संबंध में जो प्राथमिकता दी जानी चाहिये थी वह आजतक नही दी गई है। आज आप देश के किसी हिस्से में चले जाइये तो आप पायेंगे कि सबसे पहले बच्चे को जिस समय शुरू में उसको पढ़ना चाहिये, जिस समय उसको शिक्षा की जरूरत है, जिस समय उसका चरित्र बनता है, उस समय के लिए, उसके लिए हमारी सरकार की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। हमारे देश में कालेज हैं, ऊपर के स्कूल हैं, लेकिन नीचे के जो स्कूल होते हैं, जो शिक्षा उन्हें प्रारम्भ में मिलनी चाहिये सरकार की तरफ से वह नहीं मिल रही है। इस तरह की शिक्षा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा और मिशनों द्वारा दी जाती है लेकिन जो चरित्र को बनाने वाली पहली बुनियादी शिक्षा है, उसके बारे में सरकार की ओर से कोई प्रयत्न नहीं किया गया है, ऐसा मुझे लगता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिक्षा की दिशा अभी तक निर्धारित नहीं हुई है और शिक्षा का दृष्टिकोण हम अभी तक तय नहीं कर पाये हैं। उसी के कारण आज देश में इतना बड़ा असंतोष है। हमारे देश में जो विद्यार्थी समाज है वह मामूली बात में भड़क जाता है और गलत रास्ते पर चला जाता है। इसमें हमारे विद्यार्थियों का उतना दोष नहीं है। मैं यह मानता हूं

[श्री गंगाशरण सिंह]

कि जवानी उतावली होती है, उसमें जोश होना चाहिये, उसमें गतिशीलता होनी चाहिये, लेकिन उसको सही रास्ते पर चलाने का काम हमारा है। यहां शिक्षा के सम्बन्ध में कमेटियां बनीं। एक कमेटी बनी जिसके हमारे राष्ट्रपति जी अध्यक्ष थे और दूसरी कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष श्री मुदालियर साहब थे। इसी तरह से भिन्न भिन्न सूबों में भिन्न भिन्न कमेटियां बनीं। उत्तर प्रदेश में आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और शिक्षा की दिशा और रूप के संबंध में इन कमिटियों ने सिफारिशें की। इन सिफारिशों में उन्होंने कहा कि शिक्षा का जो दृष्टिकोण होना चाहिये, वह राष्ट्रीयता और जनतंत्र पर आधारित होना चाहिये। लेकिन जहां तक जनतंत्र का सवाल है, जहां तक राष्ट्रीयता का सवाल है, उन्हें शिक्षा का अंग बनाने के बारे में कोई कोशिश नहीं की गई। हमारी शिक्षा में शुरू से ही राष्ट्रीयता और जनतंत्र की बुनियादि के बारे में कोई स्थान नहीं दिया गया और उसका नतीजा यह हुआ कि आज हमारी शिक्षा की कोई आधार शिला नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है। महज अक्षरों का ज्ञान कर लेना, कुछ पुस्तकों को पढ़ लेना ही शिक्षा नहीं है।

आज हमारे सामने सबसे जरूरी चीज जो है वह यह है कि हमें अपनी शिक्षा की बुनियाद तय करनी चाहिये, शिक्षा का दृष्टिकोण तय करना चाहिये। हमारी शिक्षा जो चल रही है वह ऊपर से लैरनी हुई है और अमरलता की तरह फैली हुई है, जिसकी न कोई बुनियाद है और न कोई दृष्टिकोण है। इसलिए हमें शिक्षा के संबंध में सबसे पहले जो बात कहनी है वह यह है कि पहले हम उसकी बुनियाद तय करें, उसके दृष्टिकोण को तय करें। इस संबध में जो बड़ी बड़ी कमेटियां बनीं, उन कमेटियों की सिफारिशों का कोई परिणाम कार्यरूप में नहीं निकला। जब मैं उन बड़े बड़े नामों और कमेटियों के बाद शिक्षा की नीति और व्यवस्था पर गौर करता हूं तो मुझे इकबाल का यह शेर बारबार याद आता है:

दर्दे इन्सानी मगर या तालिबे दरमां रहां,
ई जनाब आते रहे और आं जनाब आते रहे।

राधाकृष्णन् साहिब आये, मुदालियार साहिब आये, श्री आचार्य नरेन्द्र देव आये, लेकिन शिक्षा अभी तक उसी और उसी रफ्तार से चल रही है। इस ओर हमें ध्यान देना चाहिये, यह मेरा निवेदन है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE): How much time will you require?

SHRI GANGA SHARAN SINHA: Two, three minutes more.

महोदया, पिछली बार राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलते समय मैंने जो कुछ कहा था, मेरे कई मित्रों ने इस सदन में उसका जिक्र किया और प्राइम मिनिस्टर साहिब ने भी उसका जिक्र किया। उसका जिक्र करते समय उन्होंने जो सद्भावना मेरे प्रति प्रकट की है, उसके लिए मैं उनका आभार मानता हूं। और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जो अपेक्षा उन्होंने मुझसे की है उसकी मैं अपने जीवन में चेष्टा करता हूं और भविष्य में भी करूंगा कि उसके अनुकूल बन सकूं और उस अपेक्षा की पूर्ति कर सकूं। लेकिन मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि जिस बात की ओर मैंने इशारा किया था, प्राइम मिनिस्टर साहिब ने जान बूझकर उसको छोड़ दिया। वे काफी होशियार आदमी हैं और मैं उन्हें 40 वर्षों से भी से अधिक जानता हूं, उनकी अक्ल के बारे में मुझे कोई शक नहीं है। उनकी शालीनता तथा उनकी अक्ल दोनों का मैं कायल हूं। इसलिए मैं यह समझता हूं कि जिस तरह से चक्रव्यूह के युद्ध में अर्जुन मुख्य दरवाजे से न जाकर बगल के दरवाजे से जयद्रथ को मारने चले गए, उसी तरह की नीति हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपनाई। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि मैं ने जब मुगल साम्राज्य का जिक्र किया तो मैंने यह नहीं सोचा था कि वह साम्राज्य बनाने वाले हैं। मैं स्वयं एक समाज-

वादी और जनतांत्रिक होने के नाते और उन्हें भी जनतांत्रिक समझता हूं इसलिए यह कल्पना नहीं कर सकता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साम्राज्य बनाने की चेष्टा करेंगे । अगर कल्पना भी कर पाता तो मैं यह जानता हूं कि वह शक्ति, वह ताकत, वह चीज आज के युग में सब को प्राप्त नहीं है और मैंने उसका जिक्र भी नहीं किया था । जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी उन्होंने बहुत से गलत काम किये लेकिन उनकी दिलेरी, बहादुरी, उनके त्याग और लगन का कुछ अंश भी हमारे शासकों के पास नहीं है । मेरा मतलब मुगल साम्राज्य की तरह साम्राज्य की स्थापना करने से नहीं था, मेरा मतलब तो यह था कि मुगल साम्राज्य के अन्तिम शासकों ने अपनी विलासिता और शक्तिहीनता और आपसी कलह से उस समय मुल्क की जो परिस्थिति कर दी थी, दुर्भाग्य से आज कांग्रेस सरकार वह परिस्थिति पैदा कर रही है । मेरा ताल्लुक उस परिस्थिति से था, उस साम्राज्य से नहीं था। साम्राज्य की बात अगर आप कीजिये, तो यह ठीक है कि शायद आप राजनैतिक साम्राज्यवाद नहीं फैला पा रहे हैं लेकिन जिस तरह का साम्राज्य-वाद आज हमारे देश में चल रहा है, वह राज-नैतिक साम्राज्यवाद से ज्यादा घातक है । जब मैं आज के साम्राज्यवाद पर ग़ौर करता हूं, मुझे बार-बार ईस्ट इंडिया कम्पनी के दिन याद आते हैं । आप को याद होगा और ईस्ट इंडिया कम्पनी का इतिहास पढ़ने वाले जानते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कम्पनी का कारोबार काफी आगे बढ़ गया, तो उसके जितने मुला-जिम थे, सबने अपना प्राइवेट कारोबार भी शुरू कर दिया था । उनके अपने गोले और गोदाम थे । ईस्ट इंडिया कम्पनी के जो मुलाज़िम थे, उनकी अपनी मंडियां थीं, अपने उनके नौकर थे, हर जगह उनका प्राइ-वेट कारोबार शुरू हो गया था । हमारी सरकार की भी आज यही हालत है । हमारी सरकार के जो मिनिस्टर हैं, उनका मिनिस्टर की हैसियत से कारोबार है ही, लेकिन हर आदमी का ईस्ट इंडिया कम्पनी के मुलाज़िम की तरह अपना अलग कारोबार भी है । किसी का किसी समाज के नाम पर है, किसी का किसी समिति के नाम पर है, किसी का किसी परिषद् के नाम पर है, किसी का किसी बोर्ड के नाम पर है, किसी का कोआपरेटिव के नाम पर है, किसी का सहयोग समिति के नाम पर है, और सिर्फ यही नहीं है कि आप मुगल साम्राज्य के अंतिम दिनों की याद में दिलाते हैं, आप ईस्ट इंडिया कम्पनी के दिनों की भी याद दिलाते हैं इन कारवाईयों से । ईस्ट इंडिया कम्पनी के मुलाज़िम जो करते थे, वही हमारे मिनिस्टर, हमारे कांग्रेस के लीडर और हमारी सरकार के लोग कर रहे हैं। जिन को सरकार में जगह नहीं मिली है और वह जो इस तरह का साम्राज्यवाद नहीं चला सकते हैं, वे क्या करते हैं ? उन्होंने अपना एक सौरमंडल अलग कायम कर लिया है । हम आप जानते हैं कि हम जिस पृथ्वी के रहने वाले हैं, यह पृथ्वी सौरमंडल सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है । सूर्य उसके बीच में है, और जितने ग्रह, उपग्रह हैं, वे उसके आगे पीछे चक्कर मारते हैं । उसी तरह जिनको सरकार में जगह नहीं मिली है, ऐसे जो लीडर है रूलिंग पार्टी के, उन्होंने अपना अपना सौर मंडल अलग कायम कर लिया है । सूर्य की तरह वे बीच में रहते हैं और उनके इर्द-गिर्द ग्रह-उपग्रह चक्कर मारते रहते हैं । इस देश में, केन्द्र में, हर प्रांत में, हर जिले में, हर तालुके में एक एक सौर मंडल चल रहा है, और लाइसेंस वाले, परमिट वाले, उसके वर्कर, यह, वह, और यह सब ग्रह उपग्रह अपने सूर्य के चारो ओर चक्कर लगाते रहते हैं । मेरा यही कहना है कि इस प्रकार के सौर मंडलों को समाप्त कीजिये, इस प्राइवेट एम्पायर को समाप्त कीजिए क्योंकि ये जो व्यक्तिगत साम्राज्य हैं इन समाजों, परिषदों, बोर्डों, सहयोग समितियों और कोआपरेटवों के नाम पर ये केवल आप को ही लेकरके नहीं डूबेंगे, ये देश को भी डुबावेंगे । यह इतना बड़ा पत्थर जो आपने अपने गले में बांध लिया है यह हमको, आपको और सारे देश को बिना डुबाये नहीं

[श्री गंगा शरण सिंह]

रहेगा । अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर एम्पायर कायम करना नहीं चाहते हैं तो कम से कम जो एम्पायर, जो साम्राज्य, जो रौब मंडल कायम हो गये हैं, उनको तो वे तोड़ें, जो देश का इतना अहित कर रहे हैं, जो देश का इतना नुकसान कर रहे हैं ।

उन्होंने कहा है कि देश में सब कुछ शांत है, देश में एकता है, और केवल कुछ लोगों के, पालिटिशयन्स के, कुछ राजनैतिक दलों और गुटों के दिमाग में यह विश्रृंखला और निराशा मालूम होती है । जब उन्होंने कहा तो मुझे अचानक कुछ याद आ गया । अभी मैं इतिहास की एक किताब पढ़ रहा था और उस किताब में मुगल बादशाहों का और उनके कई तरह के सिक्कों का जिक्र था । शाह आलम द्वितीय से बहादुर शाह जफर तक की बादशाहत के जमाने में सिक्कों पर फारसी में जो लिखा था उसका भी उल्लेख था । जब दिल्ली की बादशाहत डूब रही थी, उस समय भी सिक्के पर यह लिखा जाता था कि जिसका यह सिक्का है वह बादशाह सातों समुद्रों और सातों द्वीपों का बादशाह है । कहने वाले यह भी कहते थे कि सातों आसमानों का भी बादशाह है । जो बिरुदावलि गाई जाती थी, उसमें भी कहा जाता था । जब वे दरबार में आते थे, तब भी यही बातें कही जाती थीं । उसी तरह मुझे याद आता है कि यहां तो देश विश्रृंखल हो रहा है, टूट रहा है और हमारे शासक मन से सातों देशों और सातों द्वीपों के बादशाह बने हुये हैं । वही शाह आलम और बहादुर शाह के सिक्के और बिरुदावलि वाली हालत आज हो गई है । मैं दर्द के साथ कह रहा हूं । मैं इसलिये नहीं कह रहा हूं कि मुझे कुछ व्यक्तिगत रूप से लेना देना है । मैं इसलिये भी नहीं कह रहा हूं कि मुझको ख्वाहम-ख्वाह आलोचना करनी है । मैं भी घूमता हूं देश में, मैं भी मिलता हूं लोगों से और देखता हूं कि आज देश विश्रृंखल हो रहा है, आज देश में इस सरकार पर अविश्वास हो रहा है, सरकार की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, सरकार जो कुछ कहती है लोग समझते हैं उसमें कुछ छिपा कर रखा जा रहा है । इसलिये आज सबसे बड़ी जरूरत इस देश में विश्वास का संचार करने की है और इस विश्वास के संचार करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमारी सरकार और हमारी सरकार के जो लोग हैं वे ज्यादा सफाई से, ज्यादा ईमानदारी से ज्यादा बहादुरी से देश के सामने आवें । इससे तत्काल थोड़ा उनका व्यक्तिगत नुकसान हो, मगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इससे अन्त में उनका भी फायदा होगा, देश का भी लाभ होगा और देश में विश्वास कायम रखने और एक नई प्रेरणा का संचार करने का यही तरीका है । धन्यवाद ।

SHRIMATI DEVAKI GOPIDAS (Kerala) : Madam Vice-Chairman, I support this brilliant Budget wholeheartedly. It is indeed a landmark in the budgetary history of India. Our Finance Minister has to be congratulated very much for presenting this surplus Budget after giving some relief to the common man and after setting apart R s. 749 crores which is Rs. 32 crores in excess of last year's provision for our defence expenditure. The common man will certainly be greatful to him to the extent of the marginal reduction in personal taxation as also for the abolition of or for the reduction in the excise duty on certain consumer goods. In this Budget proposal, the Finance Minister has tried to combine the social objectives of the Constitution with the expansion and development of our economy. Thus he has partly succeeded in giving relief to those hit hard by the rising prices of essential at tides. In this respect there is a loss of revenue to the tune of Rs. 29.8 crores, a portion of which he has tried to make up by increasing the duties on what are called "scarce materials" and by some additional import duties, over and above the recent surcharge of 10 per cent. I hope that the impact of these on the costs of articles and our exports may be beneficial, even though this cannot be assessed now.

The changes in the personal taxation ,-ire entirely in the right direction. The relief given to the corporate sector would

help (o revive the capital market. The integration of the super tax with income tax and the reduction of tax at all levels »nd of the ceiling rates, justify the hope that there will be reduction in tax evation. The offer of 60 per cent of the unaccounted money for voluntary disclosure and the promise of keeping the names of the parties secret, appear to be a clever gesture to find out black money.

Regarding the finding out of evasion and black money, I feel that the Government can get the help of the general public if only the Government would arrange to publish the place or to whom or to which telephone number the information is to be conveyed. I am sure the Government will get the cooperation of the public if the Government will make proper and prompt enquiries and book all such miscreants. This is sure to go a long way in stopping this evil. When we consider this subject of black money we find there are people who want to gain such black money and become wealthy and get social status, without any regard to the way in which they are amassing that wealth. In fact, this is the main incentive for the people to amass such wealth, no matter whatever be the means.

Regarding the annuity scheme I have my own apprehensions as to how it will affect the limited income groups. It seems to be a matter to be investigated whether the revenue account will suffer much loss if we do away with this compulsory form of taxation, in comparison to the income that Government may get by way of increased insurance premia and savings deposits. Any way, I leave it as a suggestion to be worked out.

It is gratifying to note the honest efforts that are made to find out black money. Regarding that I would like to stress that more and more stress should be placed on moral values especially on the coming generations. At least we will have to get rid of the miscreants and the bad elements Irom society. We have also to educate the coming generations and also orient our education policy in that manner.

A fact which we cannot ignore is that even after these tax concessions, we are still under a heavy tax burden—the highest in the world. Of course, in a developing stage, one generation has to suffer for the benefit and prosperity of the coming generations and we may not grudge it. But how much and for how long? That is the question now. How to relieve the common man further so as to make him feel more confortable and secure is the real problem facing us. The prices of all essential articles and consumer goods have gone up 200 times high. I for one do not feel that with all these concessions, the prices are going to come down. It is invariably found that once the economic structure soars high, it is impossible to bring it down. On the basis of the increased cost of living, the wages of all sections have gone high. And that tells upon the cost of production and naturally, higher level of prices is stabilised, Thus, we find that it is a vicious circle from which we are unable to wriggle out. Therefore, the Government has to consider all aspects of this increased price level, liven the grants and loans given by the (iovernment to institutions and the State Governments have to be based on these calculations. Still a conscious effort here to hold the price-line and to regulate the capital market is imperatively felt by all. The relief given to the corporate sector would revive the capital market to some extent while the concessions announced in the indirect taxation would bring down the price level. All these concessions may help to give a bit of relief to the people in the limited income group who form a major section of the community.

It is heartening to note that this time even after tax concessions and setting apart enough for all the essential items of expenditure and after providing substantially for the Plan schemes of the final year of the Third Plan and for preliminary work to enable us to launch the Fourth Plan on a proper footing, our Finance Minister is able to find some surplus or savings. Along with this if we could make a conscious effort to mobilise all the resources available and avoid waste and curtail expenditure to the minimum in the civil administration and firmly deal with tax evasions, I am sure we can find more savings which can be used for the common good. When the Government is preaching frugality to the State Governments and the people, this Government is in duty bound to see that the same is practised by them. I feel that

[Shrimati Devaki Gopidas.] here in the Planning Commission and such other Government Departments so much reduction in staff can be effected. There is no use increasing the office time unless they decide to work. I know of men who were working incessantly when they were in foreign service but are sitting quiet now in the Government offices just only bossing over others. And they complain that they have no occasion to develop their capacities and utilise their initiative. May 1 ask, what sort of socialism are we having when we know there are people in public undertakings who are drawing about Rs. 1,200 salary without even paying tax and we find that our officers, especially the N.G.Os are hard pressed nowadays with the small amount of emoluments that they are getting. If we mean to bring about socialism in the country we have to see that this big gap in their emoluments is reduced. We have to fix a maximum ceiling and a minimum. We find the small officers, especially the N.G.Os, are suffering very much today because of the high cost of living. At this juncture 1 would like to remind the Finance Minister about his promise of setting up a Pay Commission to consider the question of increasing the salary scale of the N.G.Os especially of Kerala. According to the Central Pay Commission Report the Centra! N.G.Os were getting in 1958 Rs. 100 while now they are getting Rs. 135.50 plus the recent allowances sanctioned to them. In Madras it was Rs. 79 in 1958 and now they are getting Rs. 115-50. And in Kerala in 1958 it was 79 while today they are getting only Rs. 82.50. This is the position. So we will have to see that these N.G.Os are paid more because they are |invteriably the people who do (he bulk of the work in Government offices. Unless we care for them we cannot get wholehearted work out of them.

Regarding their promotion and other things also I would like to say a word. There is a confidential record kept by the Section Head and we find that those who could say "Ji Janab" and who can do crow catching get all the favours while those who are dutiful and who turn out more work are ignored. They do not get any favours because they have no Godfather or Godmother through whom they can get promotion and such other favours. We have to stop this sort of thing. We have to find out a machinery, we have to find out ways and means by which the work turned out by the officer will be the basis on which he will get promotion. If these officers are assured that their due promotion, their due benefits, are secure and they will get them without having to go in for recommendations or anything of that sort, I am sure they will sit quietly and do their work properly. So we will have to find out ways and means for this.

Now, the new provision of giving tax exemption to income upto Rs. 2,400 spent on account of institutional care to handicapped dependants is quite a welcome measure. It gives a feeling that every fringe of the society is cared for. Our aim is to provide basic amenities to all human beings. So a small investment in human beings, higher wages, better con ditions of life and availability of basic necessities of life to all have to be found. Even the common consumer goods are too costly and out of reach for the common man. So the people should be provided with the common consumer goods at subsidised rates. At this juncture I would like to say that we will have to introduce everywhere old age pension schemes, widows' pension schemes etc. as we are having in Kerala, so that those who are neglected, those who have no other means of livelihood can have a proper living in our country.

We have already launched upon certain measures to solve the food shortage, some long-term measures, but more attention has to be given to complete irrigation projects, both minor and major, and to provide enough fertiliser and distribute it to the farmer In time on crop loan basis. The Government must see that not an inch of fertile land is kept fallow and if necessary we have to pass legislation for this purpose. The farmers must be given incentive prices even by imposing a cess. Our people are ready to tighten their belts if they are sure to get a better life, say, within ten years.

Healthy body in a healthy mind is the saying. Likewise we have to give more stress on health programmes. It is commendable to note that our Health Minis-

try has risen to the occasion in giving training to health personnel and it has successfully carried out the work of eradicating almost all the communicable diseases like small pox, malaria etc. *(Time hell rings)*

Regarding drinking water, I would say it is the most essential and primary necessity of human life. In fact, almost all the diseases are contracted by drinking filthy water. Therefore a pure water supply is one of the most essential requisites for preserving the health of the nation. Prevention is better than cure and I hope our Finance Minister will see that enough amount is provided for rural water supply schemes and other health programmes.

There is one more point I would like to stress and that is about the iax concession which has been given in respect of family planning. That is a good thing *(Time bell rings)*

SHRI S. S. MARISWAMY (Madras): Madam Vice-Chairman, I am sorry I cannot associate myself with the chorus of praise that has been sung on the Finance Minister for his Budget. Of course, it is true that no new tax has been levied and also some reliefs have been given but these reliefs are nowhere near to abating the miseries and sufferings of the people. There is a proverb in Tamil to the effect that there is no use giving ginger decoction to one who has swallowed a crowbar. These reliefs are like that; they will not touch even the fringe of the sufferings of the people who are groaning under heavy taxation. So I have no word to say in praise of this Budget, nor can I join in the chorus of other people who are praising our Finance Minister for his Budget. If you ask my opinion, I will say that this Budget is a trap, a diversionary move, calculated to switch people's attention from the impending Fourth Plan which is going to sweep all of us down like a typhoon. If we look at the Budget against the background of the coming Fourth Plan, the future looks very bleak, gloomy and dismal. The country is already groaning under the weight of the previous three Plans and the morale of the people is at the lowest ebb. People like Rajaji and Shrimati Vijayalakshmi Pandit have said that we have become hundred per cent, loan-minded and aid-minded and it would seem that nothing wdl move in this blessed country without foreign aid. This is a dangerous situation- and God only knows how we are going to maintain our independence without any economic shackles. There is no answer for this crucial question in this Budget, nor is there any assurance that there will be the much-neeJed Plan holiday in which to set things right which are in a topsy-turvy position today.

Madam, if a cruel man who beats his wife every day stops doing so for a day not for any love of his wife but because that the man wants a change, can we say that he has reformed? What is the guarantee that he will not strangle her tomorrow? Today there is no imposition of new taxes, but I am quite sure that next year the Budget will come with a redoubled vigour for imposing new taxes and so long as the Fourth Plan is hanging over our heads like the sword of Damocles nothing is sure. They can come up with a supplementary demand after some time.

Now, the attention of all of us is on Kerala and we wonder what will happen to that poor State, whether a people's Government will emerge or the President's Rule will continue. From all indications, I find that the President's Rule will be continued. I may be surprising many of my friends here if I reveal a secret in this House. The President's Rule was a premeditated plan, hatched a long time ago, with a view to thwarting the chances of democratic opposition parties to come to power in that State, which has rejected the Congress totally. To explain this, I must say a little about the background of Kerala politics. On the eve of the elections, the majority of the Leftist Communist leaders were arrested in a sweep. The Government came out with an excuse for the step saying that they had unearthed certain plots of the Leftist Communists. They said that they were in league with the Chinese Communists. If it were so, this is a very serious matter which requires the Government to take any step within its power to end this traitorous role of the Communists. For that they should have banned the Party. They did not do so. They instead arrested the top leaders and left the rank and file to go scot-free. If

[Shri S. S. Mariswamy.] they had banned the Party and thereby prevented the Leftists to contest the elections, the results would have been diilerent in Kerala. You take it from me that the Congress would have been put to an even more thorough defeat there and the real democratic forces would have come to power, thereby putting an end to the President's Rule. The Government deliberately spoiled this prospect and by their foolish acts of omission and commission left the Leftists as a stumbling block for the real democratic forces in their efforts to win victory in the Kerala elections. Now, as a result of the Government's ruse, there has been confusion and the votes were divided, ending in a stalemate. This was wantonly created by the Congress Party in order to perpetuate the President's Rule. I knew fully well that this plan was sedulously nursed in Delhi by the Congress High Command with the great man, Mr. Kamraj, and was put intc* ^operation very effectively in Kerala. If the Leftist Communists have won in Kerala substantially, the credit for it goes not only to its rank and file, but also to the Congress leader, Mr. Kamraj. This reveals the intolerant and dog-in-the-manager attitude of the Congress Party. What I am afraid of is that what has happened in Kerala might be repeated elsewhere too, if things are allowed to go on like this. I would request all the Opposition Parties in India to give serious thought to this matter and find out a way to put an end to this nefarious tactics of the ruling party.

The only way out is that we must create a climate in our country wherein the Congress will be shamed out of its tactics. I hear from friends in Kerala that big industrialists, capitalists and moneyed people were actively canvassing for the Congress. It appears that they offered unlimited funds to the Party to be spent in Kerala. Did they do so out of love for the Congress and its policies? So far as I know, the only love that the capitalists have is the love for their money. So, they supported and continue to support the Congress with a view to enlarging their fortunes through the permits, licences and quotas. The Congress Party to them is a veritable *Kamadhenu* or *Kalpagavriksha* yielding the licences and permits that they need. That is why money is pouring into the coffers of the Congress. Unless this is stopped and the Congress Party is left with its own resources, as the other Parties are left with their own resources, there cannot be a real contest between the Parties. So, we must all strive to see that the licences, permits and quotas are not misused by the Government to collect funds for their Party and its election campaigns. How is this to be done? The only way is to vest the power to grant licences, permits and quotas with an autonomous Board comprising men of proven honesty, integrity and calibre. The Government might decide the policies, but this Board will put them into effect. This view has also been recommended by the Santhanam Committee.

Another problem which is equally important and perhaps more burning and vexing is our language problem. Much has been said on this subject already. Let me just narrate a dream that I had a few days ago. I dreamt that I had become all of a sudden very old and in my dream I saw several Indian young men clad in fashionable attires, introducing themselves as Ambassadors from the several States of the country. I was amused and when I asked them how they had become Ambassadors in their own country, they said that because Hindi was violently imposed on the people the country was split into many sovereign States and hence they had become Ambassadors. I was shocked at first, but was relieved to find that it was only a dream, a nightmare. All the same it came to me as a warning and I want this warning to be shared by the Government also. Even now, I am afraid, our Government has not woken up to the poignancy of the situation. It is still lingering in the realm of theory, whereas it should be opening its eyes to the conditions that prevail in the country and work out practical solutions. Conditions in the country warrant a return to the *status quo ante*, that is to say, the retention of English as the official language of India. The talk about bilingualism or three or four-language formulae will not cut ice. When I voice this view I might not be pleasing some of my friends here, but this is the only way

out of the mess we are in at the moment. Our freedom, unity and solidarity are in peril today and the enemies are sitting on our borders. This is the time when we must garner all our energy for constructive action and concentrate all our initiative on the expulsion of the enemy from our sacred •oil. We should not give room for fissi-parous tendencies to grow. Unfortunately, however, our concentration is being lavished on other minor problems and wrong solutions. I am told that some members of the ruling party are consulting astrologers as to the chances of success of Mrs. Bandaranaike, so that they might again resume negotiations through her with the Chinese.

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

It is a shame on us. If things are not set right in 1965, the enemy in our territory will become a permanent fixture and will prove to be a greater menace to us than ever. Thank you.

SHRI M. M. MEHTA (Gujarat): Madam Deputy Chairman, I rise in support of the Budget. I support it only because it is not deficit. After plenty of years we have got a Budget which is not a deficit one. This is the only merit I can see in it. It has tried to make its first impact as if to satisfy everybody, but it has totally failed to satisfy anybody. At least, it is not the Budget of a Government which is avowed to socialism. Appearance is generally deceptive, and so is the case with this Budget. If the Finance Minister had been able to present this so-called balanced Budget, it is not due only to the increase in PL 480 deposits. There is a substantial contribution from the profits of the public sector industries also at the same time, which is nearly Rs. 50 crores more than in the previous year. With all these tages, he should have given more relief to the common man and the middle class people. When we go through the pages of this Budget, we find that he has given relief first to those people who are giving income-tax and that also, as you will see, for the higher income brackets, not for the middie-class people. There is no question of relief for the lower ones. On the contrary, he could have lifted some of the excise duties on the consumer goods. It is not only by decreasing slightly the excise duty on cycles and shoes that the people can get relief.

AN HON. MEMBER: Cloth also.

SHRI M. M. MEHTA: Cloth also, but like my hon, friend, Shri Ganga Sharan Sinha, I am also convinced that the common man is not going to get cheaper cloth according to this. And there is a tricky thing behind all these cycles and shoes. What about the poor shoe-makers? What about the co-operative societies of shoemakers? Who will benefit? It is the Kanpur shoe factory, Bata and Flex, nol the ordinary man who stitches shoes in the streets. It is a jugglery of figures which may produce such a mirage before the people that the common people will gei the benefit of it. As my friend, Shri Deokinandan Narayan, said very rightly, today those people who make shoes and those people in the small-scale industries will be affected very much. He should have provided more funds for education which is the burning problem of the day. He should have provided more funds for social security. Instead of that, on the contrary, the Minister had the kindness to benefit the bigger business people by way of tax certificates and development rebates and plenty of such things. Not only that, the taxation of the corporate sector has been coming down since 1963, and at present also you will find that plenty of concessions are being given and the taxation is going low day by day. On the top of it, what a way to tap the black-market money! Between the people who have committed crimes and those who have remained honest all these years no difference is being demarcated by this method of taking out the black money. *(Interruption.)* Will you please listen? You can talk in your turn. He could have been more strict with the people who evade taxes. I have come to know—un-fortunately Mr. Krishnamachari has gone out—of a case in which the famous Jains are involved, who evade taxes. While replying in this House to questions on the Punjab National Bank, he said that its working was very fine. A man who rose from being a clerk to the post of Controller of Loans and Cash Deposits, who

[Shri M. M. Mehta.] had served that bank for 30 years, comes-forward with all the proofs that he has and says that if he cannot prove anything about the mismanagement, he is prepared to undergo any punishment that the Government will give. He can prove it by the papers themselves. There is a letter even by one of the Jains to the Manager to please send some lakhs of rupees at his place. There are tape recordings in which the Accountant himself has admitted playing fraud to the Government. There are so many things he has said. Here is the letter the Finance Minister writes that the Governor of the Reserve Bank does not see anything substantial by giving an inter view to him. I do not understand it. Ii is not a question of what the I.C.S. ring feels about it. It is what the Minister feels, whether he feels that there is a substantial thing in it or not, that should count. It is not the Governor of the Reserve Bank who can decide whether there is corruption or any such thing. They are not the people to rule if this is going to be a socialist State. I know the reason for this observation. There was an observer sent to the Punjab National Bank from the Reserve Bank. That is why it has been denied. I still request this House that if they want, I can produce that man who is prepared to undergo any punishment, who is a responsible man, who has worked in the same Bank from the post of a clerk to being the Controller of Loans and Cash Deposits. Such a responsible position he occupied

SHRI B. R. BHAGAT: Madam, since this concerns a very important bank, may I explain the position? I think I replied in this House in this very session in regard to a question that this matter was enquired into by the Reserve Bank. To say that the Governor of the Reserve Bank is an I.C.S. and therefore his words should not be relied upon, that is not the question. He functions under the Banking Companies Act. The Reserve Bank and the Governor are in charge of implementing the Banking Companies Act. They control all the commercial banks under an Act of Parliament. So, not only they should do it but it is their responsibility under the Act, and the Reserve Bank has a very well organised Inspectorate. They do checking of all the payments, normal checking which is very often repeated every month or every two months; and they do special checking also. So in this matter the Finance Minister or the Government depends upon the advice of the Reserve Bank which is equipped with all the apparatus of inspection and everything. This matter was specifically gone into by the Reserve Bank in a special enquiry, and I announce to this House that so far as the question of the bank is concerned there is no loss to the bank. The bank is not under any monetary loss. I want to repeat it again because it concerns a credit institution in which lakhs and lakhs of poor people particularly in this are involved, that nothing should be done to damage a credit institution. It has been very responsibly said that no harm has been caused to this bank. The Reserve Bank has enquired into it, and he should be satisfied.

SHRI AKBAR ALI KHAN: Particular complaints were also enquired into.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Mehta, you please continue.

SHRI M. M. MEHTA: Who enquired? First of all I would like to know that. Whom were the people who enquired into it? The people concerned themselves, because when mismanagement took place, an observer from the Reserve Bank was appointed, and under his regime . . . *{Interruption)*

SHRI B. R. BHAGAT: The observer has been withdrawn.

SHRI M. M. MEHTA: Just now I heard cur Law Minister speaking in that House. There is a fundamental rule of law that the party concerned directly or indirectly cannot sit in judgment over the issue. There is no question of importance. We have come to know of the Jains from the Vivian Bose Report. He has directly written to the Manager of the Punjab National Bank—I will produce the letter insued—-"please send so many lakhs to me". Under what ground? Not only that, bat those people who opposed this policy were victimised. And not one only. The man with a service of 30 years' standing was made to resign, and 21 other people-

had to go from this Punjab National Bank for that. So it is not that only one man has gone; so many have gone. I still repeat that that man is ready, a responsible man like him is prepared to give you in writing that if he cannot prove it, you can impose capital punishment on him. Why does not the Governor of the Reserve Bank give him an appointment and talk and discuss with him? It is not an enquiry of one side only. He should have given him an appointment and talked with him. Do you call this the socialist way of doing things when such people as the famous Jains are being protected every now and then?* I do not believe in this. This is a very sorry state of affairs. That is why it should be looked into.

Apart from that, there are three main problems facing us today, according to me. One is education; the second is the price of essential commodities, and the third you may call foreign affairs or defence. I am very sorry to say that we have nowadays Americanised not only our way of life but our thinking also. It is not the man who holds crores of rupees is a capitalist. A man may be a pauper but he may be a capitalist in his mentality. We never' fought under Gandhiji the Britishers as a nation or people. We fought against their exploitation. Today you find in every step of our life exploitation being encouraged; every situation is being exploited; everything is done for money. It is because our education is faulty. It has Riven plenty of informal education but there is no formative element in it at all. The worst thing is, what a mess we have made of our language issue. Our Education Minister comes to Gujarat, the highest authority is available to him to talk to and to take ideas and advise them; but he goes to public meetings and public places making speeches. Here are two Ministers from the South who resigned only on the language issue when they differed. Did they not fan the fire over there? This is not the way that we should go on. There is dissatisfaction of society in every strata. There is something with which everybody is dissatisfied. We should go to the root cause of all this, we should reorient all our educational policies and perhaps, if anybody asks me, I would give my opinion that it should be centralised, that no State should have its own way of thinking of a policy. The worse thing is—my friend has gone away just now—I have still to cover the points about the cowardly approach to the political problems, as our Swatantra friends have done it. They have allowed each member of their party to talk about the language problem. I know why. The same Mr. Rajagopala-chari some years ago advocated himself (he study of Hindi. He has written an introduction to a Hindi-English book that English would have to go and that it sbould be substituted by Hindi. He has asked every Southerner to learn it. But unfortunately today with the help of certain capitalists here and there and the DMK, the whole of the South has been infuriated for their personal exploitation and for their personal gain and the coun-tiy has been led on to the path of disintegration. That is why I say about education that there is something vital, very important, which requires to be done.

Similar is the case with the prices of essential commodities. It is a man-made scarcity. We talk of a bumper crop. There is plenty of crop, much more crop then we had in the previous years, even in proportion to the increase in population. But the implementation is bad enough. The zonal system and other things are there. One part of India is being treated in a different way from the other part. If any one part of the body, the finger, feels the pain, the whole body also feels it. Implementation is not good. All the hoarders escape; there must be rigorous punishment meted out to them, whoever they may be. There cannot be any exception. And at the same time the people who enforce these regulations, they go and catch all the innocent people and extort money from them. They also should be equally punished. Today I find that in my small district, the police and certain other authorities go and search anybody's house as they like, and they just take as much money as they like. It has become a routine for them actually. A series of raids are there. The police will call some gentleman and say, there was this thing in your car, your man has taken it away, and we will arrest him. They will ask him to sit there. The poor fellow has not even

[Shri M. M. Mehta.] seen a police station. Those people will demand something, he will pay it and he will get out. I do not understand these things. On the contrary, the Government has to be more rigid if they want to root out corruption from both sides, the hoarders and those who implement these regulations.

The third point I want to speak about is defence. Today the main problem is China and Pakistan. We should take lessons from our past experience. China has stabbed us in the back. We can understand it. On the contrary, we are coaxing Pakistan; we are writing heaps of protest notes. And one friend of mine from Pakistan told me that it was a routine thing and he said that the protest notes from India are thrown into the waste paper basket and are replied to in negative terms, whatever the complaint. This is the law there. I do not know how many hundreds of protest notes we have written to them.

I come from a district where there was recently an intrusion, Kutch. There is a border-line over it. The Pakistanis had come there, it was not Karimsahi but it was Kanjarkot. And today also they are sitting there. What have we done? The Chhad Bet area had been occupied by them years before. There are no roads there, there is no drinking water there. Today also the condition remains the same. I do not understand this negligence. Are we supposed to give away our land as a gift to them? They have come and occupied it there. There is not a single road there which can lead to Chhad Bet even, which can lead to Karimgunj or to Kanjarkot or to any other place. They come and still they are sitting there, and we have not occupied that Kanjarkot. They are there. What is the use of providing huge amounts for defence in the Budget and at the same time not doing anything? Do we want again to repeat the Chinese affair there? Unfortunately, T will have to say, there is so much of element there which is not loyal to India. It is very much painful. This is in our police department and everywhere. I have got a letter, original letter, written by an Inspector of Police to the so-called in-formants saying, I have given this much of money to a particular person, you go with him and get the information. The original written order it is. And actually the man to whom money has been given does not know how .to..read even. With this money, with whatever the Government and the police give, he takes Indian goods away to Pakistan, sells them there and gives our information and returns with the goods purchased there, and smuggling is going on under the pretext of defence. I would draw the attention of our Minister over here that it is a very serious problem at the border. We cannot take it lightly as we do now.

With these words, I take my seat. Thank you.

PROF. A. R. WADIA (Nominated): Madam, in spite of what my friend, Dr. Mehta, has been saying—a good deal of criticism can be made against the Budget— I am happy to say that the Budget is good and 1 should personally like to congratulate the Finance Minister. When I say this, I do not mean that the Budget is absolutely good. Unfortunately, no Budget will ever please everybody or every party. What I like in this Budget is a certain amount of fresh air, a certain freedom from all dogmas—and that is a very healthy sign—which has led to a reduction of taxation to an appreciable extent. And what pleases me more is the concluding assurance in the Finance Minister's speech wherein he says—

> "... I would appeal to Honourable Members and to all those affected by our tax system that they should treat the present Budget as an earnest of our desire to put the tax structure in this country on an enduring and rational basi

That is a very hopeful thing, Madam Deputy Chairman. I find in it a certain echo of the policy laid down by that great American, the late President Kennedy. He said—

> "The surest way to raise revenues in the long run is to cut the rates now."

The experience of a number of European countries has borne this out And although unfortunately he did not live to carry out his own policy, I am glad that his successor has been doing it, and we find that in the United States of America, personal taxation has been reduced from the range of 20 to 91 per cent, to 14 to 65 per cent, in four stages, to be completed in 1967. Even in 1965, the revenue has increased. Why? It is for the simple reason that consumers purchase more goods; the plants produce more goods; more men are employed; the investment has increased; so the profits increase and the revenue increases.

SHRI M. RUTHNASWAMY (Madras): Does the hon. Member say 'plans' or 'plants'?

PROF. A. R. WADIA: This has actually happened in the United States of America.

SHRI M. RUTHNASWAMY: Plans or plants?

PROF. A. R. WADIA: It is plants. I can tell you, it is the commonsense of the Americans and the Britishers alike. I remember that in the British days it used to be said that India was the brightest ornament in the Crown of England. And it was thought that if India was lost to England, England would lose all her economic prosperity. As a matter of fact, this has not happened so far for the simpie reason that the English people today are paid much more than they were ever before. As a result of it they have got more money to spend and more goods are produced and disposed of in England itself. In other words, I mean that England is far more prosperous today without India than she ever was with India. Now that is the policy which we ought to have in mind. Unfortunately, in recent years we have become very plan-minded and this planning has been done in a way which Is most deleterious to the interests of India.

4 P.M.

I said that there was a fresh trend in the Budget. That trend is from the egalitarian budget to a budget of production. By egalitarian budget I mean that there was a tendency to think that the high incomes should be reduced by high taxation so that the poor people might get the benefit of it. It is an absolute illusion.

I remember in this connection an interesting story of an American millionaire. I am not prepared to say that it is true—very appropriate—it may not be apocryphal—but it has got a moral of its own. A multi-millionaire was visited by a certain gentleman who extremely critical of American capitalism, and he went on to abuse the millionaires, to say that they had got so much money while people like him had got nothing at all. The millionaire listened to him very quietly, and when he had done, he asked him, "what do you estimate my wealth to be?" He mentioned several millions of dollars. He said, "What is the population of America?" He mentioned a certain figure. He divided the income by the population which came to a few dollars.* The American put his hand into his pocket, drew out a few dollars and gave it to him. He said, "This is your share of my wealth". Now this is what it comes to. Wealth is not something static to be distributed. It is always under production. Moreover special efforts have to be put in to keep up the high level. And that is the great thing which we have to remember.

Now, Madam, I feel that our economy has failed. I am inclined to agree with almost everything that *my* friend, Shri Ganga Sharan Sinha, said today about the prestige that the Government enjoys, or the bad economic condition in which our Indian population is living today. Why is it so? For the simple reason that our planning has been extremely unrealistic. For one thing, our planners forgot that people must have food. It took them nearly seven years to understand that we cannot eat iron, steel or cement. They almost completely neglected agriculture, and as a result of it we find ourselves now, an agricultural country, starving, begging for food and paying millions of rupees just for the sake of getting food from outside.

The second mistake that planning has made is an over-emphasis on heavy industries. Now I can understand our desire to compete with the most developed

[Prof. A. R. Wadia.] Western countries in the world. But there is a world of difference between what is possible and what is desirable. Our planners forgot the simple distinction between "the possible" and "the desirable", and as a result of it we have had public undertakings which are working at a loss, public undertakings which have produced very little dividend. And why? Because it is worked by people who have no business instinct in them, who have no business administration in them. They think that they can spend money in whatever way they like. And if a proof of it were wanted, we have only to read the Public Accounts Committee report to find out how they criticise the irresponsible fashion in which things are ordered before they have got any place to place these things. They remain in the open for months and months as a result of which naturally things are lost.

In the meantime there is a tremendous suspicion about the private sector as a result of which the private sector is not as fully encouraged as it should be and as a result of it one very eminent gentleman in Bombay. Mr. G. L. Mehta, said that the issue of new capital had to be underwritten. But the underwriters have become under-takers. That is the sort of thing that explains the fall, the stagnation in our capital as well as the stock exchange market. And all this is due to our wrong emphasis.

Madam, I do appreciate several things in the present Budget. The first thing that I appreciate is the relief in income-tax. But I am not quite happy with it. I think there is room for greater reduction. As I said, the lower the tax the greater will be the collection because there will be more incentive with the people to be honest in declaring their income. I am glad that the companies have got a ceiling of 70 per cent, in income. I am glad that encouragement is given to new industries by the system of Tax Credit Certificates as well as a total of five years' holiday from wealth tax.

I am glad that employers are encouraged to spend money on family planning among their employees. That is a very healthy thing to do which may not come to much. But it is a good plan which is something worth encouraging.

I am glad again that there is 10 per cent, rebate on bonus shares. But I should like to add that the tax on these bonus shares is absolutely iniquitous. It should go absolutely for the simple reason that the companies themselves are made to pay 12J per cent, on bonus shares, and I feel it is iniquitous to have a double system of taxation.

Madam, I feel that there is considerable room for improvement in the coming years and I hope that the hon. Finance Minister will keep to his promise and put things on a rational basis so that in the years to come we shall have less taxation and more revenue, most prosperity.

May I venture to submit a few suggestions? I would seriously suggest that the income tax should not go beyond 50 per cent. Our Finance Minister is so fond of following the report of Prof. Kaldor. He has adopted all the taxes that are recommended by him but he has forgotten one thing that Prof. Kaldor said. He said that all these taxes could be imposed provided income-tax is reduced to 45 per cent. Our Finance Minister has conveniently forgotten that. He has imposed all other taxes without the safeguard of 45 per cent, in income but I am prepared to go even up to 50 per cent. I venture to suggest that our income-tax system; should be simplified. There is something definitely wrong with it. I am perfectly certain that the attention of the Finance Ministry has been drawn to a certain system which has been devised by one of their own Income-tax Commissioners, Mr. R. P. Shah, and the system is so simple that the income of every assessee could be assessed in a few minutes whereas now the system is so complicated that the assessment of a single assessee takes about six to eight hours. Now the adoption of a simple system will go very far to reducing labour and it will help us a lot. Now I find, as a humble tax-payer myself, that I have not been assessed for the last 3 or 4 years. The assessments are still to come but every year the demand comes for advance payment of Income-tax. I con-

sider that to be extremely bad because in order to make me pay a certain advance they must know what my income is. There must be some basis for it but they do not pass the final orders and they say that it will be done later. That seems to be a waste of labour and it is unfair to millions of assessees, especially people of the lower middle class who have to depend on the refund that they get on their slender investment in stocks and shares.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. There are many many speakers more.

PROF. A. R. WADIA: Three minutes more please. The planning should be realistic and I venture to suggest that the Income-tax Officers should be helpful. I am told by a friend of mine who was assessed in England that the Incometax Officers there go out of their way to tell the assessees what reliefs they are entitled to. T can hardly imagine the Income-tax Officer in India doing that. He would hardly go out of the way to suggest what reliefs are possible to the Income-tax payer. I put it again finally that our Budget should be geared to production. The present system of high taxation leads to loss of initiative. People ask: 'Why should we earn more when we work till midnight and the major portion of our income is taken away by the Government?" There are doctors in Bombay who do not receive cheques. They want to be paid in hard cash. With this high taxation system there is a terrible temptation to cancel the real Income.

Lastly I come to a practical acknowledgement on the part of the Finance Minister that he has failed to get at the black money. In spite of the fact that he has created a class of informers who will act against their own employers and give secret information to the Income-tax Department so that their employers could be caught hold of and in the present Budget "he is advocating the system of making black-monied people declare their income so that 60 per cent, can go to the Government and 40 per cent, can be retained by then*. It seems that both these systems are absolutely immoral. Whatever practical value there may be from the standpoint of taxation, both are immoral but of the two, of course the system of creating informers is more immoral because it atfects the sanctity of homes, it encourages people to be practically spies within one's own family and within one's office.

Lastly I do not wish to say anything more because I have said it on previous occasions. Why does not the Finance Minister have the courage to persuade his colleagues to give up the suicidal policy of prohibition, which deprives the State of a very huge income without making people more moral in the slightest degree? On the contrary if there is a demoralisation in our society at the present moment, I think it is due to prohibition. When people get into the habit of breaking laws, they will break all laws with impunity.

कुमारी मनिबेन वल्लभभाई पटेल (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं कुछ बातें इस मौके पर कहना चाहती हूं । क्या यह बात ठीक है कि हम इतने सारे उपाय करते हैं तब भी हमारे लोगों को आज संतोष नहीं है ? इसका कारण क्या है, हमको यह सोचना चाहिये । किस तरह से हमारे लोग जीवन बिताते हैं, क्या करते हैं, कितनी मुश्किल है, यह सब हमें देखना चाहिये और इसका रास्ता निकालना चाहिये । आजादी के बाद हमारा स्वास्थ्य बढ़ा है और इस कारण हमारी मृत्यु-संख्या में भी कमी हुई है, जो पहले बाल मृत्युएं होती थीं, उसमें भी अब कमी हुई है और कुछ हमारी आयु बढ़ी । इसलिये जनसंख्या बढ़ने लगी । तो क्या जिस तरह से आज फैमिली प्लानिंग चल रहा है, इस तरह से हमें कोई लाभ हुआ है ? जिन देशों में फैमिली प्लानिंग चली है उनके क्या प्राब्लम्स हैं, इसके बारे में क्या कभी हमने जांच की है ? वहां इस कारण कितनी नयी नयी समस्याएं खड़ी हुई हैं, उसके बारे में हम क्या कभी सोचते हैं और अपने यहां यह नयी समस्या हल करना चाहते हैं ? मेरी राय में तो फैमिली प्लानिंग में जो हम पैसा डाल रहे हैं

[कुमारी मनिबेन वल्लभभाई पटेल]

उससे हमें नुकसान हो रहा है, हमारा नैतिक स्तर गिर रहा है और हम बापू जी के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से, काम करना चाहते हैं परन्तु उनका बताया रास्ता यह नहीं है, ऐसी मेरी नम्र राय है। आज अमेरिका में और दूसरी जगहों में देखिए, क्या हालत है ? वहां वृद्ध आदमी जो होते हैं उनके पास धन तो काफी होता है परन्तु उनको सन्तान की ओर से जो ममता होती है और प्रेम होता है, वह मिलता नहीं, कुत्ते बिल्ली की तरह आयु बिताते हैं—किसी तरह से जीवन बिताते हैं। क्या हम इस प्रकार का जीवन यहां लाना चाहते हैं ? हमको इसके बारे में पूरा सोचना चाहिये। आज फैमिली प्लानिंग के नाम से, कहा जाता है, कि कनाट प्लेस के फुटपाथ पर उसके साधन बिकते हैं। केमिस्ट के यहां चाहे साधन मिलें या नहीं मिलें, परन्तु फुटपाथ पर तो मिलता है। इस तरह हमारे देश की हालत रही तो हम कहां जाएंगे ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि आज हमारा फारेन एक्सचेंज कितना कम होता जाता है? हम कहते हैं कि विदेशी मुद्रा के बारे में हमारी काफी कठिनाई है, एक तरफ यह बात है, दूसरी तरफ आम जनता में हम क्या देखते हैं ? लोग क्या कहते हैं कि जब देखो तब मिनिस्टर लोग, सरकारी कर्मचारी बाहर जाते रहते हैं, विदेशों में जाते हैं, पार्लियामेंट चलती हो, तब भी वे विदेश जाते हैं, तो क्या हमारे मिनिस्टरों को और सरकारी कर्मचारियों को इतना बाहर जाने की जरूरत है, इतना जाना क्या ठीक है ? जितनी बड़ी संख्या में हमारे लोग ये जो डेलीगेशन में भेजे जाते हैं, इतनी बड़ी संख्या में इनको भेजने की क्या जरूरत है? यह सब देखना चाहिये। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने मिनिस्टरों के जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस तरह की देश में हवा बनायेंगे तो हमारी विदेशी मुद्रा बच सकती है। आज हम विदेशी मुद्रा बचाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ऐसी हवा पैदा नहीं करना चाहते हैं जिससे कि विदेशी मुद्रा बच सके, बल्कि हम उल्टी हवा पैदा कर रहे हैं।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि आज हम लोगों में इस तरह की हवा फैलानी चाहिये कि सरकार को इन्कम टैक्स देना सब लोगों का कर्तव्य है। परन्तु एक तरफ से हम देखते हैं कि जो इन्कम टैक्स लेने वाले हैं, जो इन्कम टैक्स लेने वाले कर्मचारी हैं, वे साहूकार और देने वाले सब चोर हैं और इस तरह से उनका बर्ताव रहता है। इस तरह की जो हवा है, उसको बदलना बहुत जरूरी है। कोई भी इन्कमटैक्स लेने वाला या वसूल करने वाला जो बड़ा या छोटा कर्मचारी है, वह छोटे-छोटे आदमियों को सता सकता है वह कोई भी मुद्दा निकाल सकता है कि तुम्हारे पास इतना रुपया इस साल कहां से आया और इस तरह से वह पिछले चार पांच सालों का इन्कम टैक्स मांगता है। तो मेरी यह विनती है कि इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया जाना चाहिये और इसके बारे में सोचना चाहिये। आपको इस समय उदाहरण देने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं इस समय उदाहरण दूंगी तो आप उस कर्मचारी से पूछेंगे तो वह उसका बदला अगले साल उस आदमी से लेगा, क्योंकि उस आदमी का तो उससे ही काम पड़ेगा। इसलिए आपके सामने कहना ठीक नहीं है। मेरे पास छोटे-छोटे आदमियों ने अपनी अपनी शिकायतें भेजी हैं, जो हर साल अपना इन्कमटैक्स देते हैं, हर साल देना चाहते हैं। अगर कोई सीधा सादा आदमी यह कहता है कि मेरी इस साल इतनी इन्कम हुई है, तो उसे परेशान किया जाता है कि पिछले साल क्यों नहीं बतलाया। हम इसको इस साल की इन्कम किस तरह से मान सकते हैं, इस तरह की बात कहकर इन्कम टैक्स वाले उससे पिछले साल का भी वसूल करते हैं। इसलिए मेरी खास विनती है कि इस बारे में भी सोचने की जरूरत है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है जब हम आजाद हुए थे तब सरकार ने खादी के बारे

में काफी अच्छी हवा फैलाई थी। उस समय राष्ट्रपति भवन मे खादी का उपयोग किया जाता था, सरकारी मकानों में मिनिस्टरों के वहां खादी आने लगी थी । लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज, राष्ट्रपति भवन में खादी नहीं है । सरकार की तरफ से एक सरकुलर निकाला गया था कि खास अवसरों पर सरकारी कर्मचारियों को खादी की एक खास पोशाक पहननी चाहिये । आज न राष्ट्रपति भवन में और न मिनिस्टर के यहां कोई खादी का प्रयोग करता है । सब सरकारी कर्मचारी इसको इस तरह मानें तो यह बात भी अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। मेरी यह विनती है कि आज खादी में कई तरह की वैरायटी तैयार हो गई है अब इतनी प्रकार की खादी मिलती है तब उसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा क्यों नहीं किया जाता है ? आप कई प्रकार की, कई तरह की योजना बनाते हैं लेकिन जो गरीब लोग खादी को बनाते हैं, जो सैक्शन इस काम को करता है, कोई आपकी योजना उन तक नहीं पहुंचती है । आपकी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट की योजना है वह भी उन तक नहीं पहुंचती है । खादी बनाने से लाखों और करोड़ों लोगों की आमदनी होती है और इसी करण से इन लोगों को थोड़ा बहुत पैसा मिलत । है । इसलिए मेरी विनती है कि खादी का उपयोग हम सब लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में में करना चाहिये, ताकि इन लोगों को अधिक से अधिक धन मिल सके और ये इस काम को आगे बढ़ा सकें ।

एक बात मुझे और कहनी है और वह यह है कि हम सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात करते हैं कि उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये, उत्तेजना देना चाहिये, उसकी मदद करनी चाहिये । लेकिन मैं देखती हूं कि जो लोग डेयरी या कृषि विभाग में सहकारी क्षेत्र में काम करते हैं, जब उनकी मन्डली कोई को. एप्लीकेशन किसी बारे में सरकार को देती है, तो वह सालों तक पड़ी रहती है। जब सरकार के सामने कोई फारेन कम्पनी एप्लीकेशन देती है, कोई प्राईवेट सेक्टर एप्लीकेशन देता है, तो उनकी एप्लीकेशन एक दम मंजूर हो जाती है । इन कम्पनियों में या प्राईवेट सेक्टर में जो पब्लिक रेलेशन आफिसर्स होते हैं, वे बड़ी बड़ी तनख्वाह पाते हैं और रिटायर्ड आफिसर होते हैं। लेकिन सहकारी क्षेत्र में इस तरह के कोई आदमी नहीं होते हैं जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन पड़ी रह जाती है । जब मिनिस्टर महोदय का इस बात की ओर ध्यान दिलाया जाता है, तो कहा जाता है कि हमारे ऊपर दबाव होता है कि उनको भी देना चाहिये । इस समय हमारे देश में जो बेबी फूड की शार्टेज है, वह एक आर्टिफिशियल शार्टेज है । मैं इसके बारे में पूरी जानकारी रखती हूं कि जिस प्राइवेट सेक्टर यानी जिस फारेन फर्म का इससे इन्टरेस्ट है और जिसने फूड प्राडेक्ट्स का लाईसेन्स ले रखा है, इस चीज को छिपा देने में, कमी कर देने में उसका पूरा हाथ है । कल हिन्दुस्तान टाइम्स में खबर निकली थी "A silent revolution in some U.P. villages" एक फारेन कम्पनी का जो लीवर ब्रदर्स के नाम से प्रसिद्ध है, एकदम यू० पी० के एक देहात के साथ इतना प्रेम बरस गया । कहा जाता है कि इटावा जिले में अमनपुर गांव वालों ने काली नदी में एक पुल की मांग की थी। लेकिन सरकार ने उनकी मांग को पुरा नहीं किया । लेकिन अब लीवर ब्रदर्स वहां पर पुल बना देंगे, क्योंकि देहात के लोग अपना दूध, अपनी खेती की पैदायश वह सब लीवर ब्रदर्स को देंगे । इसलिए लीवर ब्रदर्स ने गांव वालों को पुल का दान दे दिया है । आपको मालूम है कि लीवर ब्रदर्स की 7 लाख की कैपीटल है और वे हर साल 27 या 28 लाख रुपये का मुनाफा होता है, जो विदेशों को जाता है । आप जब इस तरह के फर्मों क सहायता देते रहेंगे और कहेंगे कि कोआपरेटिव सेक्टर बनाने में बहुत देर लगती है, तो कैसे

[कुमारी मनिबेन वल्लभभाई पटेल]

काम चलेगा ? आप एक तरफ इस तरह से प्राइवेट सेक्टर वालों को प्रोत्साहन देते हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि डेयरी और कृषि के बारे में सरकारी क्षेत्र में कुछ नहीं किया जा रहा है। अगर हम इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर वालों को प्रोत्साहन देते रहे तो चाहे वह उत्तर प्रदेश का किसान हो चाहे और किसी प्रांत का, वह सहकारी क्षेत्र के संबंध में तरक्की नहीं कर सकता है। मैं यह बात अच्छी तरह से जानती हूं कि इस बारे में चारों तरफ से काफी दबा हुआ है । इन कम्पनियों के पास बड़े बड़े आदमी बड़ी बड़ी तनख्वाह पर रखे जाते हैं जिनकी शासन में चलती है । जब इस तरह के आदमी प्राईवेट सेक्टर वाले रखते हैं, तो सहकारी क्षेत्र किस तरह से चल सकता है, क्योंकि उसमें तो छोटे छोटे आदमी होते हैं जिनकी कुछ नहीं चलती है । इसलिए मेरी विनती है कि सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये ।

इस जान कम्पनी को 15 लाख टन डयरी प्रोडेक्ट बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया। लेकिन इस के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा, तलाश नहीं की, जांच नहीं की, पूछा नहीं, हिसाब नहीं देखा कि 15 लाख टन का जो लाइसेन्स दिया गया था, उसका क्या हुआ ? जिस काम के लिए यह लाइसेंस बनाया गया था वह चीज तैयार हुई या नहीं इस बात को किसी ने नहीं देखा। यह जो लाइसेन्स दिया गया था, वह डेयरी प्रोडेक्ट्स बनाने के लिए दिया गया था मगर उसका चाकलेट बनाने के काम में प्रयोग किया गया और इस तरह से लाइसेन्स का दुरुपयोग किया गया । इस समय देश में जो बेबी फूड की कमी है, वह हमेशा चलती रहेगी । मैं यह जानती हूं कि अगर सरकार की यही नीति रही तो इस क्षेत्र को काफी नुकसान होगा और डेयरी प्रोडक्ट्स के मिलने में जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Your time is getting over.

कुमारी मनिबेन वल्लभभाई पटेल : मैं एक बात और कहना चाहती हूं और वह यह है कि भाषा के नाम से दक्षिण में जो बात हुई, आज भी वहां पर जो स्ट्राईक हो रहे हैं, उसके बारे में मेरी पक्की राय है कि भाषा तो एक निमित है, लेकिन उसके पीछे और चीज है। मेरी सरकार से विनती है कि उसके पीछे चाहे जो बल हो, जो चीज हो, उसकी पूरी जांच होनी चाहिये, उसकी तलाश होनी चाहिये और कानून के मातहत जो भी कार्यवाही करना उचित हो, वह की जानी चाहिये । अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे देश की एकता खतरे में पड़ जायेगी । अगर हम इस बात से डर जायेंगे, तो हमारा काम कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा ।

अभी मुझ से पहले जो भाई बोले थे, उन्होंने प्रोहिबिशन के बारे में जो कुछ कहा उनसे मेरी राय बिल्कुल अलग है । मैं मानती हूं कि प्रोहिबिशन के बारे में जो हमारे विधान में डायरेक्टिव है, उसके बारे में आज तक हमने कुछ नहीं किया । मेरी सरकार से विनती है कि एक योजनाबद्ध विकास योजना इसके बारे में बननी चाहिये, ताकि उसके अनुसार काम हो सके । हम महात्मा गांधी जी की शताब्दी मनाने जा रहे हैं, तो मेरी विनती यह है कि अगर सही माने में उनकी शताब्दी मनाना चाहते हैं तो हमें खादी और प्रोहिबिशन को सफल बनाना चाहिये तब ही हम कह सकते हैं कि हमने सच्चे मानों में राष्ट्रपिता की शताब्दी मनाई है ।

मुझे एक बात और कहनी है और वह यह है कि हमारे देश में आज इस तरह की एक हवा फैल गई है कि कोई भी किसी के बारे में आक्षेप कर सकता है । आज ला एण्ड आर्डर के बारे में अस्थिरता आ गई है, जिससे हमारे देश को काफी नुकसान होने वाला है । एक कहावत है "भय बिन होत न प्रीत" । यह पंक्ति बिल्कुल सही है । हमें बिना कारण किसी से डरना नहीं चाहिये ।

जनता हमारी है, देश हमारा है, राज हमारा है और जो भी कोई काम हम करते हैं, वह देश के लिए, जनता के लिए करते हैं और अगर हम डर के मारे कोई काम करेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो हमारे देश के लिए कोई भी खतरा नहीं आयेगा। एक आध बात मैं कच्छ के सम्बंध में कहना चाहती हूं। मैं यह मानती हूं कि जो चीन ने हम पर थप्पड़ दिया है, उसी तरह से यह कच्छ में हमें पाकिस्तान से थप्पड़ न मिले, इसके बारे में हमें पूरी तरह से सावधान रहने की जरूरत है। कुछ साल पहले जब वहां गुजरात में अकाल पड़ा था, तब मैं वहां किनारे तक, बार्डर तक गई थी। इसलिए मुझे वहां की हालत मालूम है और मैं सरकार से कहती हूं कि इस बारे में आपको सोचना चाहिये। सब कुछ हो जायेगा, अभी तो हम देख रहे हैं और अभी वह आया नहीं है, ऐसा करने से फायदा नहीं है। हमें पूरा जागृत रहने की जरूरत है और शीघ्रता से ठोस काम इसके बारे में होना चाहिये।

आखिर में, मैं कहना चाहती हूं कि यह जो इन्फार्मेशन देने का तरीका है, यह मेरी राय में बहुत गलत है और विश्वासघात करने जैसा है। जो आदमी विश्वासघात करके आपको इन्फार्मेशन दे उस के पास से इन्फार्मेशन लेना और उससे काम करना अच्छा नहीं है। यदि इसी तरह विश्वासघात होता रहा, तो आपके कर्मचारियों में और आपके तंत्र में भी कोई चीज सिक्रेट रहेगी नहीं। इसलिये यह गलत होगा कि जो विश्वासघात करे, उसको कोई शिक्षा न मिले। शिक्षा मिलने से विश्वासघात करने वाले को भय रहेगा और उसके लिए यही तरीका ठीक होगा। बाकी मेरी राय में यह चीज ही गलत है।

जो मौका मुझे आपने दिया उसके लिए धन्यवाद।

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA (Bihar): Madam, before I speak on the Budget, I would like to make one or two observations on the speech of Mr. Nausher Ali and the speech of the other gentleman belonging to my party, the Congress Party. Mr. Mulka Govinda Reddy and Shri Atul Behari Vajpayee have also dealt with and criticised the speech of Mr. Nausher Ali. I am glad there is none in the Opposition to support the red Communists and all of them are in jail except this gentleman and that I think is because of his old age.

SHRI G. RAMACHANDRAN (Nominated): What is wrong with old age? Can you say you are very young yourself?

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SiNHA: I say he has not been put in jail because of his old age, I think. I don't see there was anything for you to object to.

SHRI G. RAMACHANDRAN: He is younger than you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You are young also.

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA: I am an old man of about sixty and a young man of about sixty both. Anyway, Madam. I am surprised that a citizen of this country, particularly a Member of Parliament, should hold such views about the India-China dispute. He in his speech said that the emergency measures were promulgated because China entered our territory. That thing is there and then he says that no Communist country can invade another country and he said China is not our enemy. So whit does this mentality show? This mentality shows an utter perversity—an anti-national mentality, unpatriotic mentality, and it furnishes a good justification for the step taken by Shri Nanda with regard to the red Communists. I am sorry and I arr ashamed that our country has such people, particularly even in Parliament.

Then a Member of the Congress Party to which I belong and to which I have belonged for the last 44 years, I am ashamed to say, Madam, that he ventured and he dared to put some words into the mouth of our illustrious Prime Minister who is no more. This is bad manners, to say the least, and I do not want to speak much about it. I met the late Prime Minister and I have been very near him

[Shri Awadheshwar Prasad Sinha.] from the year 1927, after the Madras session of the Congress when he had moved the resolution about complete independence. Prom that time up till the day of his death I was one of the persons very close to him and one thing I can tell about him, Madam, and that is that he was incapable of doing anything in a clandestine manner. If he had spoken anything to America he would have taken the Cabinet into confidence and also the Congress Party and said it even in Parliament and also over the radio. He was a man who could not hide anything.

SHRI SUDHIR GHOSH (West Bengal): Is the gentleman referring to me?

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA: I am ashamed of you. I do not want to talk about it. I am ashamed that such a man should belong to my party.

SHRI SUDHIR GHOSE: I affirm once again the absolute accuracy of what I stated. What this gentleman is talking is nonsense.

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA: I am ashamed that such people are there.

SHRI ARJUN ARORA (Uttar Pradesh): On a point of order, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That will be expunged.

SHRI ARJUN ARORA: Can anybody say that it is nonsense? Is the remark of Shri Sudhir Ghosh parliamentary?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have said it will be expunged.

SHRI ARJUN ARORA. Thank you, Madam.

SHRI SUDHIR GHOSH: Is the word "nonsense" objectionable?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes.

SHRI ARJUN ARORA: It is unparliamentary.

SHRI SUDHIR GHOSH: In that case 1 withdraw the word "nonsense" and I repeat that I confirm once again the accuracy of the statement I made and it is absolutely correct.

SHRI ARJUN ARORA: Milady protests too much. A reaffirmation will not make a statement which is apparently inaccurate, look accurate.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Arjun Arora, you leave it to the Chair. You continue, Mr. Sinha.

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA: I have consulted persons nearest to the late Prime Minister since yesterday and they all say it is bunkum.

SHRI SUDHIR GHOSH: If that is so, then it is for the Government to say it, and not for my hon. friend.

SHRI AWADSHWAR PRASAD SINHA: I am ashamed that a party to which I have given my life and blood all these 44 years should have such a man in Delhi. I am ashamed of that.

SHRI N. PATRA (Orissa): Why are these two senior Members quarrelling in the House and bringing in their party matters into the House?

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA: Madam, there has been considerable appreciation in this House of the reliefs given by the Finance Minister in taxation, and at the same time there has also been a demand for more. The efforts made in the Budget to balance not merely the incomes and expenditures of the Government, but also to relate these to the overall balance in the economy have also been generally appreciated. It was surprising in this context to hear Prof. Mukat Behari Lai criticise the Budget as a retreat from Bhubhaneshwar, or from the socialist objective of the Congress. Madam, I have great respect for the Leader of the Praja Socialist Group because he was my teacher in political science and it is with profound regret that I have to refute some of the points which he made. At the same time, I would do it with the greatest respect for him. Prof. Lai in fact, began by saying

that socialism was conspicuous by its Absence in the Finance Minister's speech. I wonder if Prof. Lai has read that speech carefully. I shall presently come to the content of the Budget which is primarily oriented to the general objectives of the Plan which we have accepted. But before I do so, may I refer to what the Finance Minister stated at the very outset in his speech? I shall quote from his speech:

{THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair.]

"For seventeen long years after Independence, Jawaharlal Nehru dominated the Indian scene, giving meaning and substance to our aspirations as a nation. No aspect of our life, be it related to unity in the country, or economic planning for a better future, or the main- ' ter.ance of peace and goodwill among nations, escaped the mark of his un- , mistakable genius. Even such mundane matters as the Budget and economic policy were raised to a lofty plane, where they became instruments for advance towards a shining vision of economic independence, of prosperity with social justice. It is now left to us, to my leader the Prime Minister, to his colleagues in the Cabinet, as indeed, to hon. Members and to everyone else in the country, to carry forward the legacy of lawaharlal Nehru according to our lights. And I can only hope that the Budget I am about to present will helpi to fulfil this obligation in some small measure."

Sir, these words do not constitute any tall claims about socialism or socialist pattern of society. The Finance Minister was being modest when he said that the Budget would help to fulfil the obligations in some small measure. Looking at the Budget proposals it is difficult to escape the feeling that there is an endeavour in these proposals to advance the cause of economic growth with social justice. No or.e, not even a socialist, would deny that the primary aim of economic policy at present has to be stimulation of economic growth with stability.

The Budget provides for a substantial increase* in Plan outlay which will go up i Rs. 1,984 crores last year to Rs. 2,225 crores; increase has also been made in the assistance given to State Governments for financing their Plans. Provision has been made for pushing forward important projects in the public sector including those in steel, machinery, heavy electrical equipment, drugs and chemicals. The private sector projects must also go forward so that the balance of the economy is maintained. The Finance Minister had earlier announced a scheme of tax credit certificates to promote investments in the equity of new projects. He has followed this up with concessions in income-tax as an incentive for increasing savings, some of which could flow into equity investment in the priority sectors. In addition, specific concessions have also been given for expansion of output. There is also a scheme of tax credit certificates in regard to additional corporation tax paid by manufacturing companies over their tax liability in the base year and also a similar scheme of tax credit certificates up to 25 per cent of the extra excise duty paid by manufacturing units. Reliefs have been given to the tea industry in a modified form following the recommendations of the Tea Finance Committee. The system of development rebate has been rationalised and. a higher rate has been provided for priority industries. In order to encourage greater savings in the corporate sector also certain reliefs have been granted to private companies and a ceiling has also been set on the total tax payable by Indian companies.

Are these not measures designed to stimulate growth which is one of the main objectives of economic policy in India? Could any of these measures be construed as going against the spirit of socialism? It would be one thing if the Finance Minister had proposed a substantial cut in the public sector investment and at the same time given specific concessions for stimulation of private investment thereby upsetting the balance between the two. But this is not what he has done. I think from my point of view socialism does not mean a complete elimination of the private sector here and now. It also does not mean, contrary to what the respected Professor Sahib seems to think, a transformation of private capital into public capital. The basic features of any socialist

[Shri Awadeshwar Prasad Sinha.] programme must include a larger and growing public sector, the distribution of the burden of development equitably between the different sections of the community and a measure of social security. I have already mentioned the Finance Minister's efforts to stimulate growth both in the public and the private sectors. Let me turn to the manner in which he seeks to divide the burden among the various sections of the community.

We already have a highly progressive tax system. Not merely are our direct taxes steeply progressive, the incidence of indirect taxes is also, according to studies which have been made by the Ministry of Finance, progressive as between different income groups. Has anything been done in the present Budget to reduce the element of progressiveness in our tax structure? I submit that there is nothing in the proposals which does so. It would, of course, be pointed out that the highest marginal rate of income-tax has been reduced from 88-25 to 81-25 per cent on unearned incomes and from 82·50 to 74*75 per cent on earned incomes. Is this not, it may be argued, a measure in a retrograde direction? Any objective assessment of the burden of income-tax must take into account the widespread practice of tax evasion, especially in view of the much higher levels of income. Excessively high marginal rates of taxation tend to remain only theoretical; many industrialists try to avoid paying such high rates and escape from doing so even through illegal means by concealment of incomes. Yet the existence of high marginal rates penalises the honest tax payers. If the Finance Minister has sought to do justice as between the honest and the dishonest, is it unsocialistic?

Apart from this, the reduction in income-tax has been made all along the line and the family allowance has been raised. The exemption limit for tax now works out to Rs. 4,300 in the case of a married individual with two children as against Rs. 4,000 before the present Budget proposals. While a part of the concession in income-tax will no doubt go towards increased consumption—a relief to the common man to which even the Professor Sahib cannot object—it is to be hoped that a substantial part will go towards larger savings. The revised rate structure is also expected to reduce the extent of tax evasion.

Let me now turn to indirect taxes. It is a common misconception that all indirect taxes are necessarily paid by the poor or that all direct taxes are borne by the rich. And yet the Professor Sahib made much of the steady increase in the share of indirect taxes in the total tax revenue of Government. As a student of economics he perhaps would have noted that this is a phenomenon common to most under-developed economies. Carrying his argument to its logical conclusion, it would appear that all under-developed countries are necessarily anti-socialistic. But such a conclusion is obviously unwarranted. Direct taxes necessarily have to be restricted to the kind of incomes and properties which can be assessed to tax without excessive administrative costs. In a poor and under-developed economy the simplest taxes, from the administrative point of view, are excise duties and sales taxes since they can be collected without too much cost. Apart from these, an important consideration is the need to restrain consumption of inessential commodities or those which impinge on balance of payments. It is often forgotten that the incidence of indirect taxes on food-grains, which constitutes such a large proportion of the consumer expenditure of the masses. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : Mr. Sinha, your time is over.

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA: I will take only two or three minutes ... is negligible and that *it** the other major item—clothing—a substantial reduction has been announced in the present Budget. As I said earlier, thr incidence of indirect taxes is also progressive in India and the fact that such taxes predominate does not imply that the rich are being taxe'd less and that the poor are being taxed more.

Several other concessions in indirect taxes have also been announced by the Finance Minister. Excise duties on footwear, cycle parts, cycle tyres and tubes aud-

certain types of printing and writing paper have been removed altogether and a substantial reduction of these duties has been made in respect of cloth and vegetable product. One of the criticisms which was levelled against these reductions was that it was done in a halting manner and the Minister has suggested re-imposition of duties if the reduction is not passed on to the consumer. It is a fair criticism to say that Government is not sure if the benefit will be passed to the consumer. But the manner in which reductions have been made is also evidence of Government's desire that the reductions should benefit the common man and not the producer or the trader. One hopes that every possible measure will be taken to ensure that these reliefs are passed on to the consumer.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): I am afraid you will have to stop reading now.

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA: Just one minute.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): You have already taken more than fifteen minutes. Mr. Ramachandran.

SHRI G. RAMACHANDRAN: Mr. Vice-Chairman, I am noting that the Treasury Bench has been practically empty for a long time and equally the Opposition Benches. It seems to be an ideal field-day for a non-aligned person like myself, provided I am iappy to talk to empty benches.

SHRI B. R. BHAGAT: We are here.

SHRI G. RAMACHANDRAN: The one solitary member of the Treasury Benches has been delightfully unconcerned with what is being said by Members on the floor of this House. But at the moment there is some interest created by a controversy between two Members of a fully aligned Party talking at each other. But, Sir, this matter is very important. My friend, Shri Sudhir Ghosh, made a statement yesterday which I saw in the papers and when I met him in the Lobby today I asked him: Is this really something of which you have direct knowledge?

SHRI SUDHIR GHOSH: Please do not make any reference to private talks.

SHRI G. RAMACHANDRAN: *Yo** better sit down. Sir, I asked him whether this was something which he could vouch for and he told me most solemnly that he heard it from the mouth of President Kennedy himself.

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA: Kennedy has gone and Nehru has gone. You can say anything.

SHRI G. RAMACHANDRAN: You leave it alone. So, this is a very serious thing. If there is truth in what was said on the floor of the House, then it creates a new image of the great Prime Minister. It should not have been left to a querulous non-official to take up the challenge witk Shri Sudhir Ghosh. Somebody on the Treasury Bench, more responsible, should liave taken up this matter and told us if this is true or not. There is silence from the Treasury Bench and so it fell on the shoulders of a non-official To take up the challenge. It looks wrong. The matter is very serious and may I request you, Sir, to use your good offices, as the presiding officer of this sitting, to get from the Government tomorrow or on a subsequent occasion an authentic denial of what has been said or an affirmation? One or the other is necessary. But this is not my subject today. It came to me because I heard the controversy a few minutes ago.

SHRI AKBAR ALI KHAN: I think the Finance Minister will reply to it.

SHRI G. RAMACHANDRAN: I hope *he* will reply.

SHRI B. R. BHAGAT: Somebody will reply.

(Interruption.)

SHRI G. RAMACHANDRAN: Do not break lance with me on this point.

SHRI SUDHIR GHOSH: You are quite right in saying that, but if anybody has *to* say anything on this subject, it is for the Government to say.

SHRI G. RAMACHANDRAN: My lime is limited and I must not give it now to you or to any other Member. Sir, the Finance Minister must be suffering from' a surfeit of praise from almost everybody

[Shri G. Ramachandran.] and particularly at the time the Budget was presented and a few days since I remember reading nothing but praise in the newspapers. But just now, after the first glow of satisfaction aud happiness, criticism is manifesting itself and I am quite sure as we proceed with the debate *on* the Budget there will be more criticism. On the whole, let me say this, that we have not had a Budget in the last many years which has created at many levels in this country a sense of greater happiness and contentment than the present one. I am wondering why. I would like to study it more and find out. This Budget has really brought, if I may say so, a great deal of support to the Congress Party in areas and In circles where there was till now some distrust and suspicion of the Party. In any case, I am willing to join with others and" say to the Finance Minister, "you have made a new type of Budget and presented it very ably and let me congratulate you."

After having made these general observations, let me say a few words in regard to the food problem. Recently, a very responsible member of the ruling Party and no less a person than Shrimati Vijayalakshmi Pandit, who came back from the United States some time ago, addressing her Party members, is reported" to have said that as she went about in other countries it was her impression that people were saying that India has become too much loan minded and was borrowing and borrowing and that the image of India in the outside world was not too good. Somebody here quoted that Shri Rajagopalachari also has said the same thing. Shri Rajagopalachari, however is in opposition and probably this stick is a good one for him to beat the congress with. But this criticism from Shrimati Vijayalakshmi Pandit is another matter. Keeping that in mind and then looking at the food problem, it appears that there is some substance in this kind of view that might be expressed in this country. We are taking food from other countries, enormous quantities of food, hundreds of thousands of tons of wheat and rice. Probably this is unavoidable and there is nothing else that we can do now in a crisis. But we are not satisfied that, from a long-range view of the situation, adequate steps are being taken to make this country self-sufficient in food. Eighteen years after the freedom of "India we are begging .for food, right and left, throughout the world. This is a very serious matter and I am quite sure that Government is aware of the seriousness of this matter. But we on the floor of this House are not satisfied that adequate steps are being taken to ensure, as early as possible, self-sufficiency in food. My able friend, Shri Subramaniam, said the other day that land is being given to tobacco which should go to grow rice. It is not only tobacco. There are many other money crops which go into areas where till yesterday rice was growing or wheat was growing. Long ago, Mahatma Gandhi talked about "Balanced Cultivation" in this country. He wanted to map out the whole area, to find out our specific needs, and to give preference to food crops and then only to anything else. When he said that and when this was followed by drastic proposals in regard to it, by my friend, Dr. J. C. Kumarappa, people said that all this was some kind of obscurantism. In the modern world money crops are very necessary. Foreign exchange and all the rest of it are involved etc. But today none other than the Food Minister of the Government of India, faced with this crisis in food, is pleading that land must go back to food crops. It is not only cash crops but if you look round the cities, you will find buildings encroaching steadily and increasingly upon agricultural land. And then somebody said here that every inch of land is precious. I do not think that this Government has made a full over-all plan for balanced cultivation in this country. Something is going on. There is no co-ordinated agricultural effort yet at different levels, so that preference is always given to food crops. My first criticism, therefore, is that even while, with great ability we are managing to turn the corner at present in the food situation, we have not made the necessary plan to make India self-sufficient in food as early as possible. Then, there is something else equally important in regard to this matter, *i.e.* the food habits of the people. Unless we are able to bring about a successful revolution in the food habits of the people, the food problem is going to face us again and again. We eat too much grains. This is

neither good for us nor for the nation and there is no educational programme worth the name to carry conviction to the people that we have to change some of our food habits. Put altogether, as I look into the immediate future and also at the long-range future, I am not satisfied that we are doing what is absolutely necessary in the field of food production.

5 P.M.

Now, Sir, within the next few minutes which you will give me and after which you will ring the bell, let me refer to the problem in Kerala. That is my home State. I was in the thick of the freedom battle in Kerala, and I was in the first Congress Cabinet, I was a member of the Cabinet of the Thanu Pillai Government when it was first established. I speak with some knowledge of my State. I am afraid, Sir, that the ruling Party and the Central Government have bungled and bungled the situation in Kerala, bungled it so much that it looks almost irreparable today. The Kerala elections are again over. We were told on high authority even within 24 hours before the elections began that the Congress was going to come back in sufficient numbers to rule the State. Now we know what has happened. Nearly 40 so-called left Communists were elected. A slightly smaller number of the official Congressmen got through. A new body called the Kerala Congress has clearly come into the picture. Every day the situation is getting more confused. The other day I saw a cartoon in the Deccan Herald. There is in it Kerala offering an alliance to Shri Kamaraj Nadar and Shri Kamaraj Nadar turns away down the alliance, and on the top is written "the perpetual bachelor". "The perpetual bachelor" in politics is a hopeless thing. I do not think any Party in this country in the coming years can say: "I will not work with another Party to run the Government", and yet this is what is being said by the Congress and the result is a very confused situation in Kerala. I am afraid again that nothing that is being now done is going to correct the situation. Take the ca«e of the left Communists. Somebody said here that there is no difference really between the left Communists and the right Communists. I am not an authority on that subject, I leave it to the pandits to decide. But you allow these left Communists to stand for the election when they were in prison. The people who voted them into the seats in the Legislature knew that these people were in prison. Mr. Shankar, old friend whom I know well was the trump card in the hands of the official Congress. He was defeated by a left Communist who was in prison. What does it mean? This is a vote of the people against keeping these people chained down in the prisons today. I am not a Communist and I do not need to be a Communist. As long as I hold on to Gandhiji I have something much bigger than Communism. But this is a terrible disgrace to democracy in this country that you can shut up without trial, elected people like this. They are elected and you do not allow them to function. This will appear as cutting at the democratic process in this country. This may give the ruling party some dividend now but in the long run this is going to weigh against you very heavily. Something has to be done. On the floor of this House and on the floor of the other House pressure must be put on the Government to act decently in a very difficult situation of this kind. Supposing the left Communists come out, they are not going to turn the world upside down. They once ruled Kerala, and they did not do anything extraordinary and even so they were turned out by a mass uprising in Kerala. Why do the Government take up the onus of frustrating democracy, Kerala is posing a problem, and if we do not solve the problem wisely, considerately and sympathetically now, there will be in the body politic of this country this cancerous growth which will be so dangerous that it can infect the whole of India. On the one hand therefore there is the sin of commission and on the other the sin of omission, and in between we have to find a way out. It is a very dangerous situation, and I hope that wiser counsels will prevail. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHAKGAVA): The House stands adjourned till 11 A.M. on Friday.

The House then adjourned at five minutes past five of the clock till eleven of the clock on Friday. the 19th March 1965.